



Hindi/English Medium
निर्माण IAS



NITI
Aayog



नीतिआयोग

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20



निर्माण प्रकाशन

नीति आयोग रिपोर्ट-2019

नीति आयोग का गठन और संरचना

- राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
- नीति आयोग भारत सरकार की नीतियों से संबंधित प्रमुख थिंक टैंक है, जो निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
- यह भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए, केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
- यह भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है, और जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

नीति आयोग का वर्तमान संघटन

1. अध्यक्ष: श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री

2. उपाध्यक्ष: डॉ. राजीव कुमार

3. पूर्णकालिक सदस्य:

- i. डॉ. वी के सारस्वत
- ii. डॉ. रमेश चंद
- iii. डॉ. विनोद कुमार पॉल

4. पदेन सदस्य:

- i. श्री राजनाथ सिंह - रक्षा मंत्री
- ii. श्री अमित शाह - गृह मंत्री
- iii. श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कारपोरेट मंत्री
- iv. श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री

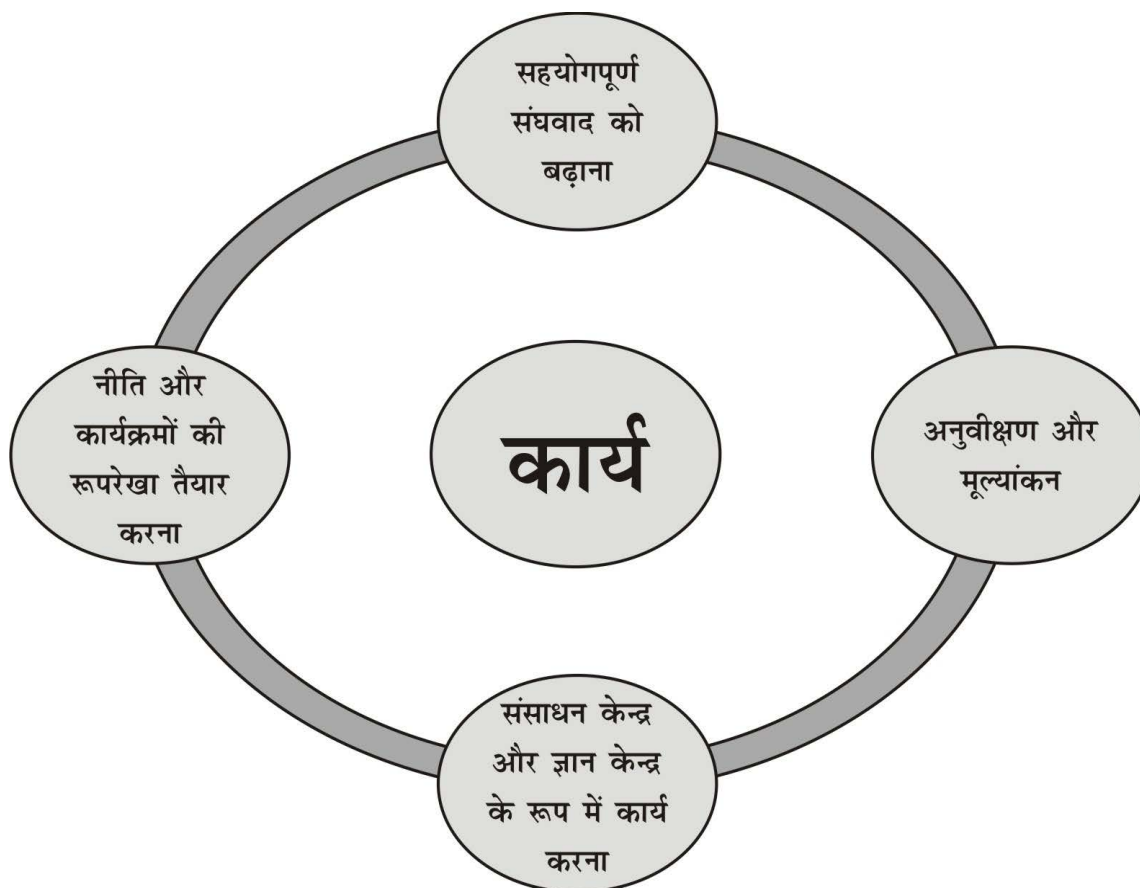
5. विशेष आमंत्रित

- i. श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री
- ii. श्री थावर चंद गहलोत-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
- iii. श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री
- iv. श्री राव इन्द्रजीत सिंह, साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

उद्देश्य

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करता है:-
 - सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
 - ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना।
 - जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना।
 - हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभांवित न हो पाने का जोखिम हो।
 - कार्यनीतिक और दीर्घावधि नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना।
 - निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम से लिए गए सबक नवोन्मेषी सुधार में उपयोग किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी आवश्यक हैं।
 - महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
 - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तियों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवोन्मेष, उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना।
 - विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।

- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना, जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ उसे हितधारकों तक पहुंचाने में भी मदद करे।
 - आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ-साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
 - कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना। राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना।
- कार्य**
- i सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ाना
 - ii नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना
 - iii अनुवीक्षण और मूल्यांकन
 - iv संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना
- ☞ नीति आयोग के समस्त कार्यकलापों को दो मुख्य केन्द्रों- टीम इंडिया हब तथा ज्ञान और नवोन्मेष केंद्र के बीच विभाजित किया गया है। ये दोनों केंद्र नीति आयोग की कुशल कार्यपद्धति का मुख्य आधार हैं।
 - ☞ टीम इंडिया हब 'सहयोगपूर्ण संघवाद' को बढ़ावा देने तथा 'नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने' के अधिदेश को कार्यान्वित करता है।
 - ☞ यह नीति आयोग को राज्यों के साथ इसके कार्यों के संबंध में अपेक्षित समन्वय और सहयोग प्रदान करता है।
 - ☞ ज्ञान और नवोन्मेष हब अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का अनुरक्षण करने, सुशासन और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर अनुसंधान का भण्डार बनने तथा उन्हें हितधारियों तक पहुंचाने के साथ-साथ कालेजों, विश्वविद्यालयों, थिंक-टैंक और स्वदेशी तथा विदेशी गैर-सरकारी संगठनों सहित समस्त प्रमुख हितधारकों को सलाह देने और भागीदारियों को प्रोत्साहित करने के अधिदेश की पूर्ति सुनिश्चित करता है।



नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय

विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय

- ❶ तत्कालीन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) का विलय करके 18 सितंबर, 2015 को विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) का गठन किया गया था।
- ❷ नीति आयोग को सौंपे गए मूल्यांकन तथा अनुवीक्षण कार्यों के अधिदेश की पूर्ति के लिए नीति आयोग के तत्वावधान में संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान

- ❶ राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) नीति आयोग के अधीन एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है।
- ❷ यह अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान के नाम से 1962 में स्थापित किया गया था।
- ❸ नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसकी महापरिषद के अध्यक्ष के रूप में और सीईओ, नीति आयोग कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- ❹ इस संस्थान के प्राथमिक उद्देश्य अनुसंधान, आंकड़े संग्रह करना, मानव पूंजी योजना के सभी पहलुओं में शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मानव संसाधन विकास, अनुवीक्षण और मूल्यांकन हैं।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

- ❶ डॉ. बिबेक देबरॉय - अध्यक्ष
- ❷ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों पर काम करती है।
- ❸ परिषद समय-समय पर आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री/प्रधान मंत्री कार्यालय को सलाह देती है।
- ❹ 2017-20 से तीन वर्षों के लिए क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (सीएलसीएस-टीयूएस) की निरंतरता, 2019-20 की अवधि के लिए लघु जल-शक्ति विकास कार्यक्रम की निरंतरता, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, अटल नवोन्मेष मिशन आदि जैसी विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
- ❺ ईएसी-पीएम द्वारा देखे जाने वाले अन्य मुद्दों में औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जेंडर और चाइल्ड बजटिंग, अवसंरचना वित्त, स्वास्थ्य/शिक्षा/महिला और बाल विकास, क्षेत्रीय विनियामक प्राधिकरणों की समीक्षा/विलय, बीमा क्षेत्र का दायरा बढ़ाना, कौशल विकास एवं रोजगार और व्यवसाय विकास शामिल हैं।

- ❶ दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर, ईएसी-पीएम को 26 सितंबर, 2019 से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक निम्नलिखित के साथ पुनर्गठित किया गया है:

नीति और कार्यक्रम ढांचा

1. आकांक्षीय जिला कार्यक्रम का रूपांतरण
2. पोषण में सुधार
3. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
4. कृषि क्षेत्र में सुधार
5. शिक्षा क्षेत्र में सुधार
6. राष्ट्रीय ऊर्जा नीति
7. भारत के स्वर्ण बाजार में परिवर्तन

परिचय

- ❶ नीति आयोग, मानव और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों की साझा दृष्टि के विकास में राज्यों, नागरिक समाज और अन्य थिंक टैंकों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक एकीकृत भूमिका निभाता है।
- ❷ नीति आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, कार्यनीतिक और दीर्घावधि नीति और कार्यक्रम की रूपरेखाओं और पहलों को तैयार करना, और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करना।
- ❸ नीति आयोग नवोन्मेष और सहयोग के माहौल को बढ़ावा देने में और सेक्टरिय लक्ष्यों को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
- ❹ यह नीति-निर्माण और कार्यान्वयन के मर्म में नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी, उद्यम और कुशल प्रबंधन को एक साथ लाने का प्रयास है।

आकांक्षीय जिला कार्यक्रम का रूपांतरण

- ❶ जनवरी 2020 में आकांक्षीय जिला कार्यक्रम (एडीपी) के सफल कार्यान्वयन के दो वर्ष पर होने पर सभी हितधारकों -
 - केंद्र और राज्य सरकारों,
 - जिला प्रशासन,
 - गैर-सरकारी संगठनों,
 - निजी भागीदारों,
 - सिविल सोसाइटी और
 - आम जनता के प्रयासों को समन्वित करके आरंभ किया गया।
- ❷ यह उल्लिखित है कि नीति आयोग ने 112 चिह्नित जिलों से 49 मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) के मासिक आंकड़े एकत्र करके और पिछले एक महीने में की गई वर्धित प्रगति पर उन्हें सूचीबद्ध करके इस कार्यक्रम के प्रस्तोता भूमिका निभाई है।

- इन 112 जिलों में भारत की 14% आबादी निवास करती है, यह शासी सुधार हेतु आकांक्षीय जिला कार्यक्रम को अत्यंत पहुंच और प्रभाव के लिए सबसे बड़ा डेटा-संचालित प्रयोगशाला बनाती है।
- आकांक्षीय जिला कार्यक्रम की रूपरेखा तीन स्तंभों पर टिकी हुई है:
 1. केंद्र तथा राज्य स्कीमों में अभिसरण लाना
 2. केंद्र तथा राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और
 3. आकांक्षीय जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- इन लक्ष्यों को तीन मुख्य कार्यकर्ता के बीच समन्वय के माध्यम से प्रभावित किया जाता है: नीति आयोग, केंद्र तथा राज्य प्रभारी अधिकारी और जिला अधिकारीकलेक्टर (डीएम डीसी) के नेतृत्व में जिले की टीमों।
- नीति आयोग की भूमिका में
 1. 112 जिलों, प्रभारी अधिकारियों, प्रमुख मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों का समन्वय और सुविधा,
 2. चौपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड और जिलों की मासिक रैंकिंग निर्धारित करना,
 3. सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा और निगरानी करना और
 4. प्रतिकृति के लिए अन्य जिलों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है।
- केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अपने संकल्प के लिए चुनौतियों और कार्यनीतियों की पहचान के लिए नियमित रूप से बुनियादी रिपोर्ट प्रदान करके जिला टीम और नीति आयोग के बीच एक स्थायी संबंध के रूप में कार्य करते हैं।
- दूसरी ओर, राज्य प्रभारी अधिकारी कार्यक्रम के समग्र मिशन के साथ राज्य की कल्याणकारी स्कीमों के अभिसरण को सनिश्चित करते हैं।
- डीएमडीसी के नेतृत्व में जिला टीम
 1. कार्यक्रम कार्यान्वयन
 2. डैशबोर्ड पर आंकड़े एकत्र करना और अपलोड करना और
 3. नीति आयोग में परियोजना प्रबंधन एकक के साथ समन्वय करके कार्रवाईपरियोजना प्रस्तावों की योजना बनाने के लिए प्राथमिक कार्यकर्ता है।
- पिछले दो वर्षों में, यह कार्यक्रम परिपक्व हो गया है और दीर्घकालिक सफलता के संकेत देता है। उदाहरण के लिए, इन जिलों में नवोन्मेषी सर्वोत्तम प्रथाओं का एक विशाल समूह उभर कर आया है।
- सर्वोत्तम प्रथाओं का एक बैंक बनाकर, यह विभिन्न जिलों के प्रशासन की योजनाओं और दृष्टिकोण को पूरा करता है और समान चुनौतियों से जूझ रहे अन्य जिलों द्वारा उनकी प्रतिकृति के लिए इन प्रथाओं पर आवश्यक सूचनाओं का विस्तार करता है।
- पिछले दो वर्षों के दौरान, एडीपी ने इन जिलों में विभिन्न महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों में स्पष्ट और सतत सुधार का नेतृत्व किया है।
- परिवर्तन की गति में विविधता है, परंतु दिशा स्पष्ट है: प्रसव पूर्व देखभाल (एएनसी) पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है, जो मातृ और शिशु मृत्यु दर को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।
- इसी प्रकार, क्रियाशील महिला शौचालयों के साथ स्कूलों की संख्या परिपूर्ण होने के समीप है।
- इस कार्यक्रम ने अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं की नामांकन दरों में भी वृद्धि की है।
- इस कार्यक्रम की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि जिला टीमों में ताजी ऊर्जा, उत्साह और आकांक्षा को बढ़ावा देकर इन जिलों में कम वृद्धि और कम प्रेरणा के दुष्चक्र को सफलतापूर्वक तोड़ना है।
- अतिसक्रिय अधिकारियों को एडीपी छत्र के तले परिवर्तनकारी बदलाव लाने की चुनौती लेने के लिए नियमित रूप से इन जिलों में नियुक्त किया गया है।
- राज्य सरकारें डेटा-संचालन शासन के इस मॉडल को ब्लॉक स्तर पर विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं और सभी केपीएल के लिए राज्य औसत मूल्यों को समरूप बनाने के लिए आकांक्षीय जिलों हेतु समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं।
- स्वयं एडीपी डिजाइन के अलावा, ऐसे अतिरिक्त उपाय, इन विकासाधीन पॉकेटों के बीच उत्तम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के माध्यम से शासी सुधार लाने और अधिक जोर देने के लिए हैं।

पोषण क्षेत्र में सुधार

1. पोषण अभियान पर द्वितीय द्विवार्षिक रिपोर्ट

- महिला और बाल विकास प्रभाग की तकनीकी सहायता इकाई को पोषण अभियान की प्रगति से अवगत कराने के लिए द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी का अधिदेश दिया गया है।
- इस अधिदेश के तहत, दूसरी द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार कर और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साझा की गई।

- ❖ अभियान के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति को दर्शाते हुए इसमें एक कार्यान्वयन सूची शामिल है।
- ❖ पोषण अभियान के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की संबद्धता।
- ❖ पोषण चैम्पियन के रूप में पंचायती राज संस्थान (ग्राम परिषद) के सदस्यों को जुटाने के लिए, नीति आयोग और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने एआईआईएमएस, टाटा न्यास, पिरामल फाउंडेशन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआई), यूएनआईसीडीएफ और समूचे देश के 30 लाख प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान के साथ भागीदारी की है।
- ❖ इस पहल की महत्वाकांक्षा ऐसे सदस्यों को सक्रिय बनाना है, जिससे वे अपने समुदाय तथा हमारी ग्राम पंचायत की पोषण कहानी जैसी पोषण कथा से व्यक्तिक रूप से अभियान का वृहत् स्वामित्व लें।

राष्ट्रीय पोषण माह की अवधारणा और आयोजन

- ❖ नीति आयोग ने मार्च और सितंबर 2019 के महीनों में समूचे देश में राष्ट्रीय पोषण माह तथा पोषण पखवाड़े की अवधारणा और आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- ❖ पोषण माह को मनाने का उद्देश्य देश के कोने-कोने तक पोषण का संदेश पहुंचाना है।
- ❖ पोषण माह 2019 में पांच घटक थे बच्चे के पहले 1,000 दिन, रक्ताल्पता-मुक्त भारत, डायरिया रोकथाम, वाँश (या धोना, स्वच्छता और सफाई) और पौष्टिक आहार (पौष्टिक भोजन)।

2. पोषण अभियान के अंतर्गत भारत की पोषण चुनौतियों से संबद्ध राष्ट्रीय पोषण परिषद:

- ❖ यह शीर्ष निकाय समग्र नीतियों को तैयार करता है और जीवन-चक्र की पहुंच को उजागर करते हुए सभी पोषण-आधारित स्कीमों का नेतृत्व और निगरानी करता है।
- ❖ यह भारत की पोषण चुनौतियों का समाधान करने हेतु नीति-निर्देश प्रदान करने के लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय और समीक्षा करता है।
- ❖ राष्ट्रीय परिषद की 2019 में दो बार बैठक हुई तथा निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया:
 - i. पोषण अभियान के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्मार्टफोन और विकास उपकरणों की शीघ्र खरीद।
 - ii. पोषण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए माताओं, शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में व्यवहार परिवर्तन का महत्व।

- iii. राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दो जिलों में दो प्रायोगिक परियोजना ब्लॉकों में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आईसीडीएस के तहत टेक-होम राशन के बदले नकदी अंतरण संबंधी एक प्रायोगिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

3. राष्ट्रीय तकनीकी पोषण बोर्ड से संबंधित कार्य :

- ❖ नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में महिलाओं और बच्चों के पोषण के विषय में नीति-आधारित मुद्दों पर तकनीकी, उत्तरदायी और साक्ष्य-आधारित सिफारिशें प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी पोषण बोर्ड का गठन किया गया था।
- ❖ राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड की तीसरी बोर्ड बैठक 12 अप्रैल, 2019 को आयोजित की गई थी। यह भारत में बाल्यावस्था और मोटापे के शिकार किशोर पर एक वैज्ञानिक परामर्श था।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

- ❖ नीति आयोग ने पीएमजेएवाई की अवधारणा पर विस्तृत कार्य किया, जिसके कारण केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई।
- ❖ नीति ने स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संगठनात्मक और शासी ढांचे को आकार देने में भी भूमिका निभाई।

श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान और निवेश

- ❖ पीएमजेएवाई के आरंभ और 500 मिलियन लाभार्थियों के साथ, अगले 10 वर्षों में 0.64 मिलियन अतिरिक्त बेड की आवश्यकता होगी।
- ❖ वर्तमान में, देश में 14,379 अस्पताल हैं, जिनमें 6.34 लाख बेड हैं। हमें 3 गुना अधिक विकास की आवश्यकता है, परंतु मुख्य रूप से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों पर प्राथमिक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ❖ निजी कार्यकर्ताओं (लाभकर और अलाभकर दोनों) की देखभाल मानकों को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना में आपूर्ति-मांग अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- ❖ यह और अधिक अस्पतालों के तेजी से निर्माण की आवश्यकता को दर्शाता है।
- ❖ अस्पताल की देखभाल तक पहुँच प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए –
 - विशेष रूप से गरीबों और समाज के बहिष्कृत वर्गों के लिए द्वितीयक और तृतीयक देखभाल,

- नीति आयोग, निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ परामर्श करके,
- स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में निजी कार्यकर्ताओं के साथ उपलब्ध क्षमता का लाभ उठाने की दिशा में काम कर रहा है तथा
- अस्पतालों के निर्माण और विनियामक वैधानिक अनुपालन के लिए भूमि प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं और वित्तीय सीमा को समझ रहा है।

पीएमजेवाई के अलावा जनसंख्या के लिए योगदायी बीमा स्कीम का विकास

- एनएसएसओ सर्वेक्षण के 71 वें दौर के अनुसार, 80% भारतीय किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और केवल शहरी आबादी के 18% (सरकार द्वारा वित्त पोषित 12%) तथा ग्रामीण आबादी के 14% (सरकार द्वारा वित्तपोषित 13%) शामिल हैं।
- पीएमजेवाई में 40% आबादी शामिल है। शेष आबादी को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- नीति आयोग असम्मिलित आबादी को शामिल करने के लिए एक योजना तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जो संभवतः गरीब नहीं है और अक्सर गरीबी रेखा वर्ग से ऊपर के वंचित समझा जाता है।
- आबादी का यह भाग, योगदान के लिए वित्तीय क्षमता होने के बावजूद, विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय से ग्रस्त रहता है जो अनिवार्य रूप से उन्हें गरीबी रेखा से नीचे धकेल सकता है।
- इस मिसिंग मिडिलर का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में तथा अधिकतर शहरी क्षेत्रों में स्थित है।

2. फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उपकरण सेक्टर में सुधार

फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण में सुधार:

- नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा सस्ती दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों (एससीएएमएचपी) संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों के मूल्यों से संबंधित सिफारिशों की गई।
- यह समिति स्व-प्रेरणा से अथवा फार्मास्यूटिकल विभाग, एनपीपीए तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध या सिफारिश पर जांच के लिए मामले को उठा सकती है।
- व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) समिति की पहली

बैठक फरवरी 2019 में आयोजित की गई थी, जिसमें व्यापार-मार्जिन-कैपिंग रूट के माध्यम से गैर-अनुसूचित दवाओं के लिए मूल्यों निर्धारण ढांचे पर विचार-विमर्श किया गया

व्यापार करने में आसानी

- नई दवा विनियमन के अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:
 - नई दवा विनियमन के अनुमोदन की प्रक्रिया के लिए विभिन्न निकायों- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के अंतर्गत आनुवंशिक कार्यसाधन समीक्षा समिति (आरसीजीएम),
 - पर्यावरण,
 - वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी),
 - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) आदि की सिफारिशों अपेक्षित हैं।
- नीति में लिए गए निर्णय के पश्चात, संबंधित मंत्रालयों द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू की गई थी।
- इनमें शामिल हैं:
 - स्टेम सेल और सेल-आधारित उत्पादों के निम्नलिखित चिकित्सकीय उपयोग (वाणिज्यिक उपयोग) के लिए दिशानिर्देश विकसित करने का कार्य।
 - जीन-थेरेपी अनुसंधान दिशानिर्देश आईसीएमआर द्वारा विकसित किए गए हैं और 19 नवंबर 2019 को सार्वजनिक रूप से जारी किए गए हैं।
 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवा और नैदानिक परीक्षण नियम 2018 के प्रारूप को अधिसूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक द्वारा मानद अनुमोदन करने के साथ 30 दिनों के भीतर बाजार प्राधिकरण देने का प्रावधान है।
- उद्यमियों, नवोन्मेषकों और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माणकों तक पहुंच जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने अपने प्रश्नों के शीघ्र समाधान के लिए एकल मंच के माध्यम से भारत सरकार के संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए बायोमेडिकल उपकरणों के स्टार्ट-अप और नवोन्मेषकों के लिए एक सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित किया।

कृषि क्षेत्र में सुधार

किसानों की आय को दोगुनी करना

1. भारतीय कृषि में परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन नीति आयोग की

पांचवीं शासी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में भारतीय कृषि में परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की घोषणा की। समिति में यह भी शामिल है:

- समिति ने कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम और आवश्यक वस्तुओं के लिए अपेक्षित संशोधनों पर जोर देने की आवश्यकता सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि में तेजी लाने, कृषि में अधिक निवेश के साधन लाने, ड्रिप सिंचाई पर आर्थिक सहायता, जल संरक्षण पर बल दिया।
- समिति कृषि क्षेत्र में सुधारों को अपनाने और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय भी सुझाएगी।

2. पीएम-आशा सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

- ☞ 2018-19 के बजट में एक घोषणा की गई थी कि केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से नीति आयोग एक सरल तंत्र विकसित करेगा, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य मिल सके। जिसमें चयनित कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन के तंत्र अथवा किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के कुछ अन्य तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।

3. जीरो बजट प्राकृतिक खेती (जेबीएनएफ)

- ☞ नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की अध्यक्षता में प्राकृतिक खेती के स्कोप और संवर्धन के बारे में चर्चा की गई।
- ☞ पद्मश्री सुभाष पालेकर, जो प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि कैसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती जैविक खेती से अलग है।
- ☞ राज्य मौजूदा कृषि-सेक्टर स्कीमों के सेट के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।
- ☞ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सत्रहवीं लोकसभा के पहले बजट भाषण में बैक-टू-बेसिक्स एप्रोच के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बात की। तदनुसार, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 12 लाख हेक्टर क्षेत्र तथा 600 क्लस्टरों को शामिल करने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में अखिल भारतीय मोड में आरंभ करने की योजना बनाई।

4. ग्राम भंडारण स्कीम को प्रोत्साहन

- ☞ ग्राम भंडारण योजना के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों पर चर्चा करने के लिए 07 मई, 2019 को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।
- ☞ ग्राम-स्तरीय भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के तरीकों पर गंभीर रूप से चर्चा की गई थी।
- ☞ चर्चा में यह उल्लेख किया गया कि ग्राम भंडारण स्कीम को उत्पादन की बुनियादी चार श्रेणियों का समाधान करना चाहिए:
 1. अनाज जैसी कठोर खाद्य फसलें
 2. जल्दी खराब होने वाली सामग्री को लंबे समय तक रखना
 3. जल्दी खराब होने वाली फसलें
 4. कपास, ऊन, औद्योगिक फीडस्टॉक जैसे उत्पाद, जो गैर-खाद्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम करते हैं।
- ☞ यह आगे उद्धृत किया गया था कि प्रशीतित ग्राम भंडारों में पेरिशैबल्स रखने से एक उपयुक्त फसल के बाद की आपूर्ति श्रृंखला के विकास को बढ़ावा नहीं मिल सकता है, बल्कि इससे बाजार चौनलों को आपूर्ति लाइन स्थापित करने में समस्या होने में देरी होगी, जिससे संकट टल सकता है।
- ☞ यह सुझाव दिया गया था कि ग्राम भंडारण और कटाई उपरांत सुविधाएं मुख्य रूप से ग्रामीण कृषि बाजार में एपीएमसी और कृषक इंटरफेस के रूप में स्थापित की जा सकती हैं, जो देश के किसी भी बाजार या उपयोगकर्ता अथवा संगठित भंडारण को पूर्व-अनुकूलन और संपर्क प्रदान करेंगी।
- ☞ यह भी निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय जियो-इंफॉर्मेटिक्स केंद्र के सहयोग से एक पोर्टल बनाएगा और जियोटैगिंग वेयरहाउस के लिए तंत्र विकसित करेगा, जिसमें समूचे भारत में कोल्ड स्टोरेज के लिए बेस-लाइन सर्वेक्षण में किए गए प्रशीतित शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा में सुधार

- ☞ नीति आयोग उच्चतर शिक्षा विनियामक ढांचे में सुधार करने के लिए चुनौतियों की पहचान करने और योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- ☞ हाल के वर्षों में यूजीसी के नियमों और दिशा-निर्देशों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए सुधारों के पहले चरण के बाद, नीति आयोग उच्चतर शिक्षा के लिए नए संसदीय कानून हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिसका प्रारूप उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है।

नीति की मुख्य सिफारिशों में निम्न शामिल हैं:

- ❶ मानक सेटिंग, वित्त पोषण और प्रत्यायन को अलग करना अपनी कवरेज, विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए प्रत्यायन ढांचे को सुदृढ़ करना उच्चतर शिक्षा में विनियामक निकायों की बहुलता और अतिव्यापी अधिदेश को संबोधित करना संस्थानों के लिए केवल न्यूनतम मानदंडध्मानक निर्दिष्ट करने के लिए विनियामक, ताकि नवोन्मेष के लिए स्वायत्तता और स्कोप प्रदान किया जा सके।
- ❷ निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (विश्वसनीय प्रत्यायन से संबद्ध) जवाबदेही के साथ स्वायत्तता संस्थानों के बीच संयुक्त डिग्री का प्रावधान।

आकांक्षीय जिलों में शैक्षिक सुधार

- ❶ शिक्षा आकांक्षीय जिला कार्यक्रम के परिवर्तन के तहत एक महत्वपूर्ण विषय है और सभी विषयों के बीच इसे सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है।
- ❷ ज्ञान भागीदारी के माध्यम से, नीति आयोग स्कूली शिक्षा में भाग लेने वाले समुदाय को बढ़ाने तथा शिक्षा तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जन आंदोलन, जिलों के परिवर्तन को फैला रहा है।
- ❸ इन आंदोलनों से स्कूली बच्चों की संख्या में कमी आई है। पुस्तकालयों की स्थापना और शिक्षण सहायक (बीएएलए) के रूप में भवनों के विकास जैसी पहले विभिन्न जिलों में शिक्षण परिणामों में आनंदपूर्ण शिक्षण माहौल और सुधार करने को बढ़ावा दे रही हैं।
- ❹ इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाल संसद शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर प्रेरणा और नेतृत्व की भावना पैदा कर रहे हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार**राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2019 का प्रारूप**

- ❶ प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।
- ❷ राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के मसौदे पर 17 मई, 2017 को हुई बैठक में प्रधानमंत्री स्तर पर विचार-विमर्श किया गया।
- ❸ नीति को दो अध्यायों सब्सिडी, क्रॉस-सब्सिडी और कराधान और ऊर्जा क्षेत्र के शासन का पुनर्गठन को सम्मिलित करके संशोधित किया गया।
- ❹ टाइम होरिजन 2040 से 2030 तक संशोधित किया गया। संशोधित एनईपी जून 2018 में अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित की गई।

भारत के स्वर्ण बाजार का परिवर्तन

- ❶ भारत के स्वर्ण बाजार परिवर्तन संबंधी एक समिति का गठन नीति आयोग द्वारा निर्यात, आर्थिक विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु इस बाजार की क्षमता को टैप करने के उपाय सुझाने के लिए किया गया था।
- ❷ समिति की रिपोर्ट फरवरी 2018 में प्रस्तुत की गई।
- ❸ केंद्रीय बजट 2018-19 ने यह भी घोषणा की कि एक व्यापक स्वर्ण नीति गठित की जाएगी, जो इसे एक परिसंपत्ति के रूप में विकसित करेगी। तत्पश्चात, इस पर विचार-विमर्श करने के लिए अप्रैल 2019 में सचिवों की एक समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

निरगानी और मूल्यांकन**1. आउटपुट परिणाम निरगानी ढांचा****परिचय**

- ❶ नए भारत में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण समग्र शासन संरचना का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए, निष्पादन को ट्रैक करने में सक्षम होना, परिणामों को यह समझने के लिए कि कोई योजना कितना अच्छा निष्पादन कर रही है, निर्धारित करना और खराब निष्पादन के कारणों का पता लगाने और कार्यप्रणाली सुधार के लिए सिफारिशें उत्पन्न करने में सहायक होना महत्वपूर्ण है।
- ❷ इसके लिए न केवल डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है, बल्कि सीमित सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को मजबूत करने और योजना हस्तक्षेप के गहन और व्यापक प्रभाव हासिल करने में मदद करने के लिए परिमेय मापदंडों के साथ उचित फ्रेमवर्क की व्यवस्था करनी पड़ती है।
- ❸ अपने संगत कार्य क्षेत्रों में अन्य वर्टिकल्स के साथ ही नीति आयोग जो विकास निरगानी और मूल्यांकन का कार्यालय अथवा डीएमईओ है, उचित निरगानी और मूल्यांकन के माध्यम से शासन में गहरी जवाबदेही का कार्य भी निभाता है।
- ❹ डेटा विश्लेषण द्वारा समर्थित प्रभावी विश्लेषण और बेहतर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नीति आयोग ने कई सामाजिक क्षेत्र सूचकांक और डैशबोर्ड विकसित किए हैं।

विकास की निरगानी और मूल्यांकन कार्यालय

- ❶ 18 सितंबर 2015 को पर्व कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का विलय करके विकास निरगानी और मूल्यांकन कार्यालय को नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था।
- ❷ इसे केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित कार्यक्रमों और पहलों के मूल्यांकन की निरगानी और संचालन के लिए अधिदेश दिया है।

वित्त वर्ष 2019-20 में की गई गतिविधियों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(i) छत्र केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन

- मार्च 2020 के अतिरिक्त पंद्रहवें वित्त आयोग के चक्र में यूसीएसएस की निरंतरता पर विचार करने के लिए, डीएमईओ को 28 यूसीएसएस के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए अधिदेश दिया गया है।
- डीएमईओ 10 मूल्यांकन अध्ययन सलाहकार पैसेजों:
 - i) कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन
 - ii) महिला और बाल विकास
 - iii) मानव संसाधन विकास
 - iv) शहरी परिवर्तन
 - v) ग्रामीण विकास
 - vi) पीने का पानी और स्वच्छता
 - vii) स्वास्थ्य
 - viii) रोजगार और कौशल
 - ix) जल संसाधन, पर्यावरण और वन
 - x) सामाजिक समावेश कानून और व्यवस्था और न्याय वितरण के माध्यम से यह कार्य कर रहा है।

(ii) आउटपुट परिणाम निगरानी ढांचा (ओओएमएफ)

- भारत सरकार में परिणाम आधारित निगरानी को मजबूत करने के लिए, डीएमईओ टीम ने 2018-2019 में निष्पादन-परिणाम आधारित ढांचे (ओओएमएफ) में सुधार के लिए एक कठोर प्रक्रिया अपनाई तथा पुनः 2019-20 के लिए आरंभ की।
- इस ढांचे का उद्देश्य सीमित सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को मजबूत करने और स्कीम हस्तक्षेपों के गहन और व्यापक प्रभाव को प्राप्त करना है।
- इसने केंद्रीय सेक्टर और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 600 से अधिक परिव्ययों में लगभग 5000 निष्पादन और परिणाम संकेतकों के लिए रूपरेखा तैयार की गई।
- यह ढांचा केंद्रीय बजट 2019-20 के साथ संसद में पेश किया गया था।
- ये स्कीमें लाभार्थियों को सरकारी सेवा वितरण का प्राथमिक तरीका बनाती हैं, जिसमें 2019-20 में 27.9 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट में से 12 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं।
- इस वित्तीय परिव्यय को स्कीम के निष्पादन के मात्रात्मक माप के साथ जोड़कर, यह उम्मीद की जाती है कि अधिक विवेकपूर्ण उपयोग और अधिक जवाबदेही को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(iii) अवसंरचना सेक्टर समीक्षा डैशबोर्ड और निष्पादन ट्रैकर्स

- प्रधानमंत्री द्वारा 14 अवसंरचना सेक्टरों और तीन सामाजिक सेक्टरों में अवसंरचना सेक्टरों की समीक्षा की जाती है।
- संबंधित मंत्रालय और/अथवा विभाग, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा के लिए, वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के लिए त्रैमासिक प्रगति आंकड़े अपडेट करते हैं।
- यह पूर्व समीक्षाओं से उभरने वाले कार्यवाई बिंदु को भी ट्रैक करता है। संबंधित नोडल मंत्रालयों द्वारा प्रदान की गई कार्यवाई की रिपोर्ट को पीएमओ के उपयोग के लिए प्रस्तुत की जाती है।

(iv) क्षेत्र के माध्यम से शीघ्र निष्पादन आकलन

- कार्यक्रम मूल्यांकन का उद्देश्य विकास कार्यक्रमों के दीर्घकालिक प्रभावों, कार्यक्रम के निष्पादन के विभिन्न चरणों में सफलताओं और विफलताओं के क्षेत्रों और कारणों की पहचान भविष्य के लिए मध्य-पाठ्यक्रम सुधार और प्रसार अध्याय का सुझाव देने का एक उद्देश्य मूल्यांकन है।
- मूल्यांकन के मापदंडों में प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, साम्यता और सेवा वितरण की स्थिरता, परिणाम और प्रभाव शामिल होंगे।

1. चैंपियंस ऑफ चेंज, आकांक्षीय जिले

- आकांक्षीय जिला कार्यक्रम नियमित रैंकिंग के माध्यम से 112 जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने पर निर्भर है, जो सक्रिय और महीने भर में किए गए वर्धित (डेल्टा) सुधार को दर्शाता है।
- डैशबोर्ड पर नवीनतम आंकड़े दर्ज करने के लिए जिलों को अपने आंकड़ा संचयन और रखरखाव तंत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी जिलों को अपने वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- इस कार्यक्रम की परिकल्पना की निष्पक्षता, लोक सदस्य डैशबोर्ड वेबसाइट पर लाइव रैंकिंग देखने के साथ-साथ संपूर्ण डेटासेट को संकेतक-वार या जिले-वार विकल्प के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- नीति आयोग सहित केंद्रीय मंत्रालयों को जमीन परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक को कुछ जिले आवंटित किए गए हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार आंकड़े डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।

2. पोषण

- नीति आयोग ने पोषण डैशबोर्ड विकसित किया है, जो राष्ट्रीय औसत के साथ विभिन्न राज्यों के निष्पादन की सहज तुलना करके भारत में कुपोषण से संबंधित समग्र स्थिति का बहुत अच्छा परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

- ❖ यह डैशबोर्ड, गर्भावस्था के समय से शुरू होने वाले विभिन्न पोषण और बाल स्वास्थ्य मापदंडों संबंधी जानकारी प्रदान करके, किसी विशिष्ट राज्य के अनेक जिलों का गहन विश्लेषण करने में भी सहायता करता है। 10 वर्षों में विभिन्न इनपुट और आउटपुट मापदंडों की तुलना मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के रूप में की गई है, जो उन राज्यों को दर्शाता है, जिन्होंने अधिकतम सुधार किया है।

3. अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला

- ❖ अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला (एटीएल) डैशबोर्ड 'माई एटीएल' समूचे देश में एक सिंगल स्नैपशॉट ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थिति प्रस्तुत करता है।
- ❖ डैशबोर्ड, किसी विशेष राज्य के जिलों में एटीएल उपलब्ध कराकर गहन जानकारी प्रदान करता है।
- ❖ किसी विशेष जिले के स्कूल की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है जैसे स्कूल बोर्ड सहयोगी भागीदारों, सोशल मीडिया हैंडल आदि से संबंध है।

4. एसडीजी भारतीय सूचकांक 2019-20

- ❖ सूचकांक के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड को नया रूप दिया गया है। नया डैशबोर्ड राष्ट्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आंकड़े एकत्र करने तथा प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक कल्पना और विश्लेषण टूल आयोजित करता है।
- ❖ डैशबोर्ड सरकारों, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंकों और शिक्षाविदों को उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में अधिक सहायता करेगा, जिसका उपयोग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एसडीजी ढांचे के तहत तेजी से प्रगति के लिए कर सकते हैं।
- ❖ यह सूचकांक नीति संवाद पर ध्यान देने, निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक साधन के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है और वैश्विक स्तर पर मान्यता योग्य मैट्रिक्स के लिए विकास कार्यवाई की दिशा में बढ़ रहा है।

प्रमुख निष्पादन संकेत

- ❖ सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की खोज में, नीति आयोग विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों, जैसे कि जल, शिक्षा, पोषण, के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए विकासशील संकेतकों पर जोर दे रहा है।

एसडीजी भारत सूचकांक

- ❖ नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को भारतीय सूचकांक में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का दूसरा संस्करण जारी किया। भारत, एसडीजी से संबंधित प्रगति के सरकार-नीत, उप-राष्ट्रीय माप वाला विश्व का पहला देश है।

- ❖ यह सूचकांक 2030 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का व्यापक दस्तावेज है।
- ❖ सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जो इस ग्रह और इस पर रहने वाले जीवधारियों के जीवन को खतरे में डालने वाली असंख्य चुनौतियों के लिए वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया है।
- ❖ लक्ष्यों का निर्धारण सभी मनुष्यों की भलाई तथा समृद्धि और सभी ईकोसिस्टमों एवं वर्तमान तथा भावी जीवन के उत्कर्ष के लिए तैयार किया गया है।
- ❖ भारत मानव सहित वनस्पतियों तथा जीवों की असंख्य प्रजातियों का घर है, और एसडीजी प्राप्त करने में इसकी सफलता विश्व के लिए महत्वपूर्ण है।
- ❖ भारत इस जिम्मेदारी से अच्छी तरह अवगत है कि उसने एसडीजी ढांचे को अपनाया है तथा अपने विकास एजेंडे को एसडीजी के साथ लक्ष्यों और इसके लक्ष्यों की समयबद्ध उपलब्धि को पूरी तरह से संबद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ❖ तथापि, एसडीजी कार्यवाई को राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
- ❖ देश के संघीय ढांचे, और संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन तथा जिम्मेदारियों के विभाजन को देखते हुए, एसडीजी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने के लिए राज्यों को अग्रणी भूमिका निभाना अनिवार्य है।
- ❖ नीति आयोग देश में एसडीजी को स्वीकार करने और निगरानी के प्रबंधन के अधिदेश का वहन करता है। नीति आयोग 'निर्धारित मापदंड की पूर्ति' मंत्र पर विश्वास रखता है।
- ❖ यह, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद विचारधारा से संबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप एसडीजी भारत सूचकांक की अवधारणा है कि एसडीजी प्रगामी दुनिया का पहला सरकार-नीत, उप-राष्ट्रीय परिणाम है।
- ❖ यह एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करता है।
- ❖ सूचकांक का प्रथम संस्करण दिसंबर 2018 तथा दूसरा संस्करण 30 दिसंबर 2019 में प्रारंभ किया गया था।
- ❖ सूचकांक के लिए इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन वाला एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो सार्वजनिक डोमेन में है।
- ❖ सूचकांक एक कार्यप्रणाली को अपनाता है, जिसमें प्रत्येक एसडीजी की स्थिति समूचे देश और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के निष्पादन 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है, जहां 100 का अर्थ लक्ष्यों को प्राप्त करना है और 0 बदतर निष्पादन को दर्शाता है।

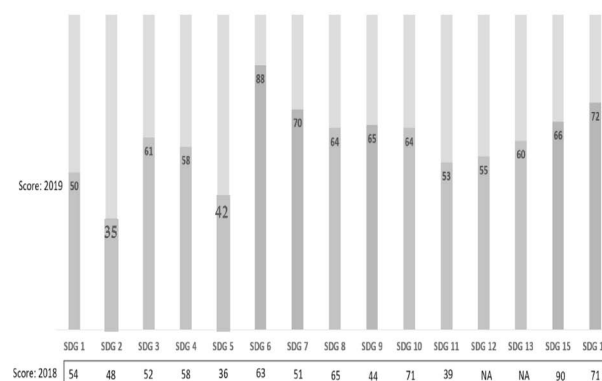


परिणाम

- सूचकांक के 2019 संस्करण के अनुसार भारत के लिए समग्र स्कोर 60 है, जो कि 2018 के 57 स्कोर की तुलना में बेहतर है।
- उच्चतम स्कोर एसडीजी 6 (स्वच्छ पानी और स्वच्छता) में 88 तथा एसडीजी 2 में सबसे कम स्कोर (पोषण और भूखमरी रहित) प्राप्त हुआ था।
- 2018 से 2019 तक का सबसे बड़ा सुधार एसडीजी 6 (25), 7 (19) और 9 (21) में हुआ है। एसडीजी 6 में सराहनीय सुधार का श्रेय स्वच्छ भारत अभियान तथा जल जीवन अभियान की सफलता को दिया जा सकता है।
- एसडीजी 7 में वृहत्त रूप से प्रगति सौभाग्य योजना के तहत घरों के सार्वभौमिक विद्युतीकरण और उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के प्रावधान के परिणाम है। एसडीजी 9 में उन्नति का श्रेय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शामिल बस्तियों, डिजिटल समावेश और इंटरनेट और मोबाइल पैठ में उठाए गए सराहनीय कदमों को दिया जा सकता है।
- एसडीजी 9 के तहत हुए सुधार से ईज-ऑफ-डूइंग व्यवसाय की वैश्विक रैंकिंग 2018 में 77 से 2019 तक 63 भारत की प्रगति को दर्शाती है।
- समस्त राज्यों में से, केरल ने 70 के स्कोर के साथ पहला

रैंक प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश 69 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। संघ राज्य क्षेत्रों में, चंडीगढ़ ने 70 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा पुडुचेरी 66 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

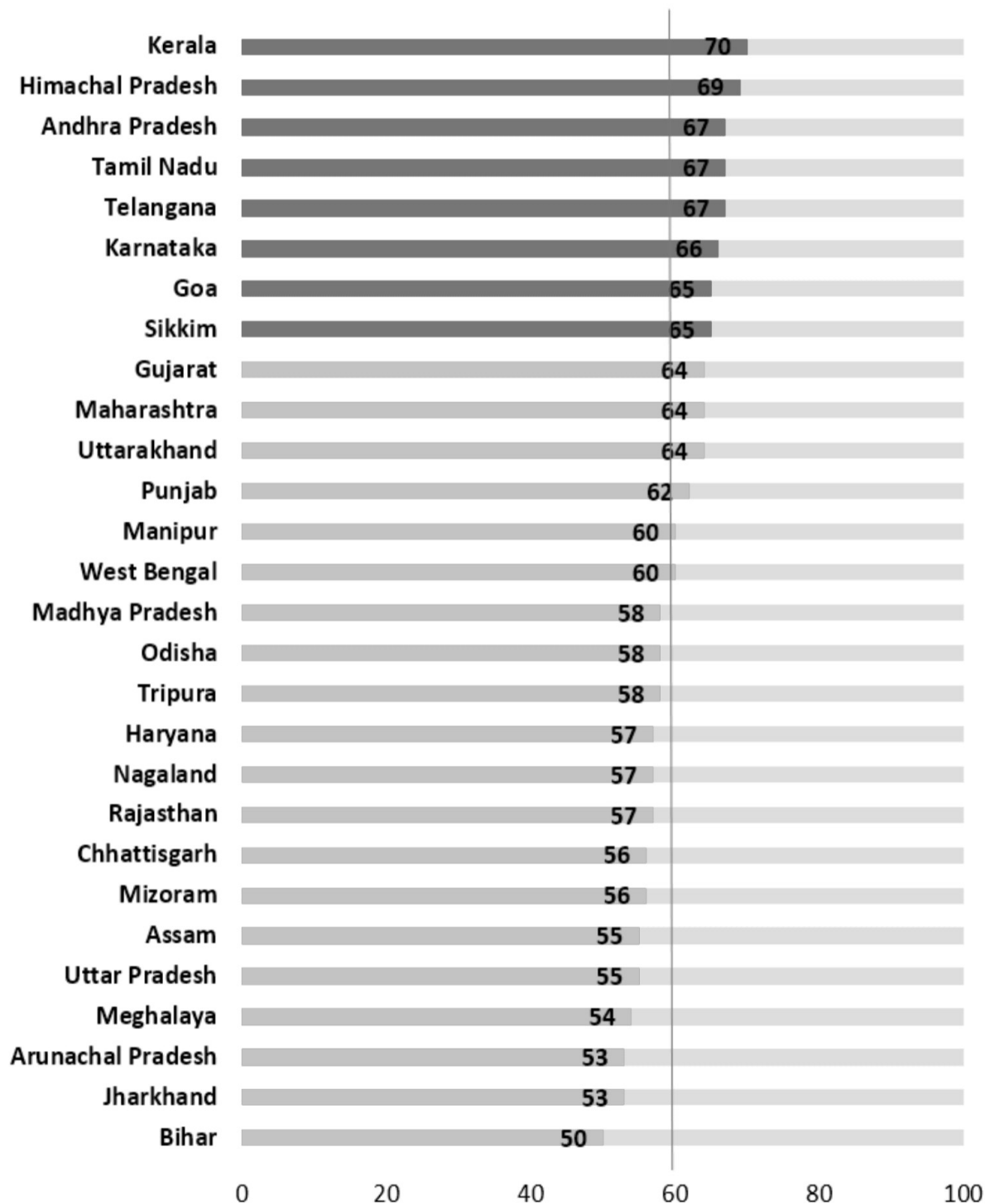
- दिल्ली नौ संघ राज्य क्षेत्रों में से 61 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहा।
- तीन राज्य – आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और तेलंगाना – 67 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार क्रमशः 53, 53 और 50 के स्कोर के साथ तालिका में सबसे नीचे रहे।



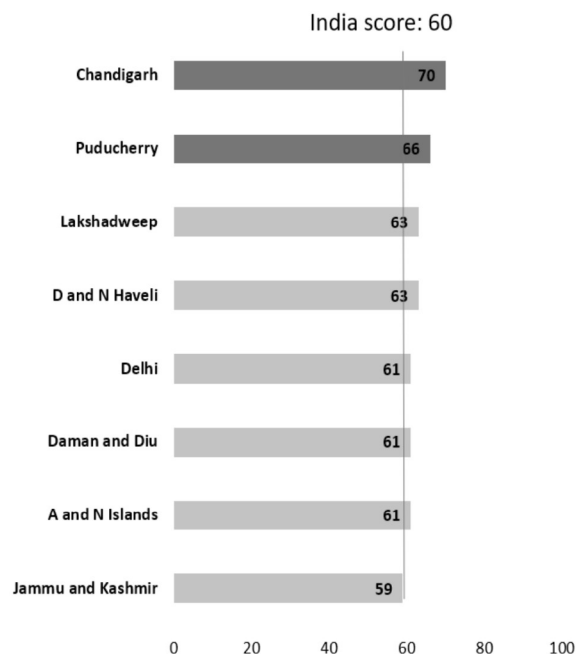
चित्र 1: 2019-20 के लिए देश में लक्ष्य-वार स्कोर। 2018 में सबसे नीचे वाले बॉक्स में संख्या स्कोर दर्शाते हैं।

STATES

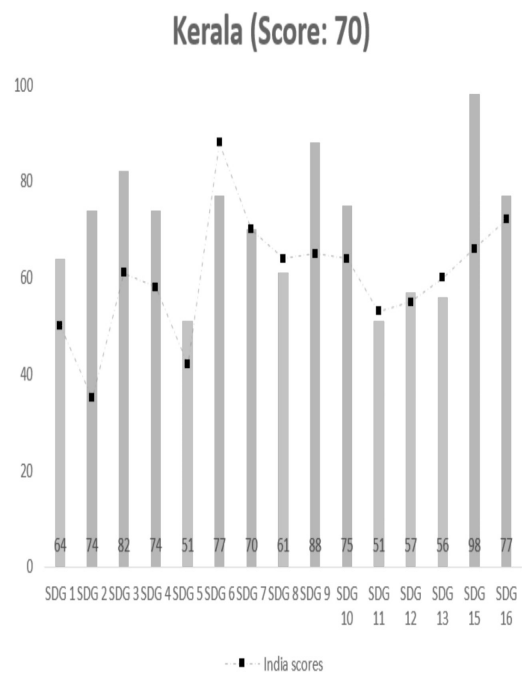
India score: 60



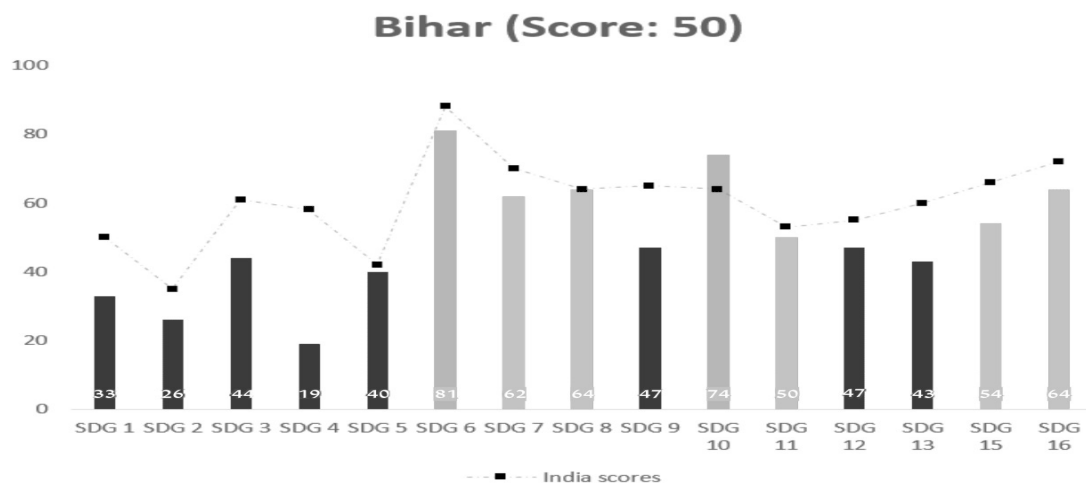
UNION TERRITORIES



चित्र 3: संघ राज्य क्षेत्र-वार स्कोर



चित्र 4: केरल का लक्ष्य-वार स्कोर, तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य तथा देश स्कोर (लाइन)



चित्र 5: बिहार का लक्ष्य-वार स्कोर, तालिका में निचला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य तथा देश स्कोर (लाइन)

सुधार:

- ➔ 2018 में 50 से कम स्कोर करने वाले सभी तीन राज्य (असम, बिहार और उत्तर प्रदेश) और आकांक्षी की श्रेणी में अपने स्कोर में 50 से ऊपर सुधार करने वाले तथा 50 से 64 के बीच

स्कोर के साथ शर्कर्ता की श्रेणी में स्नातक पूरा करने वाले।

- ➔ दोनों राज्यों (आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम और तेलंगाना) सहित 50 और 64 के बीच वाले पांच राज्यों ने 2019 में 65 या अधिक स्कोर प्राप्त किए हैं, इस प्रकार कर्ता श्रेणी से फ्रंट रनर तक पहुंचे हैं।

States	2018 Rank	2019 Rank	Direction of change
Kerala	1	1	▲
Himachal Pradesh	1	2	▼
Tamil Nadu	3	3	▲
Andhra Pradesh	4	3	▲
Goa	4	7	▼
Gujarat	4	9	▼
Karnataka	4	6	▼
Maharashtra	4	9	▼
Telangana	9	3	▲
Punjab	10	12	▼
Uttarakhand	10	9	▲
Manipur	12	13	▼
Mizoram	12	21	▼
Rajasthan	12	18	▼
Chhattisgarh	15	21	▼
Sikkim	15	7	▲
West Bengal	17	13	▲
Haryana	18	18	▲
Tripura	18	15	▲
Madhya Pradesh	21	15	▲
Meghalaya	21	25	▼
Arunachal Pradesh	23	26	▼
Nagaland	23	18	▲
Odisha	23	15	▲
Jharkhand	26	26	▲
Assam	27	23	▲
Bihar	28	28	▲
Uttar Pradesh	29	23	▲

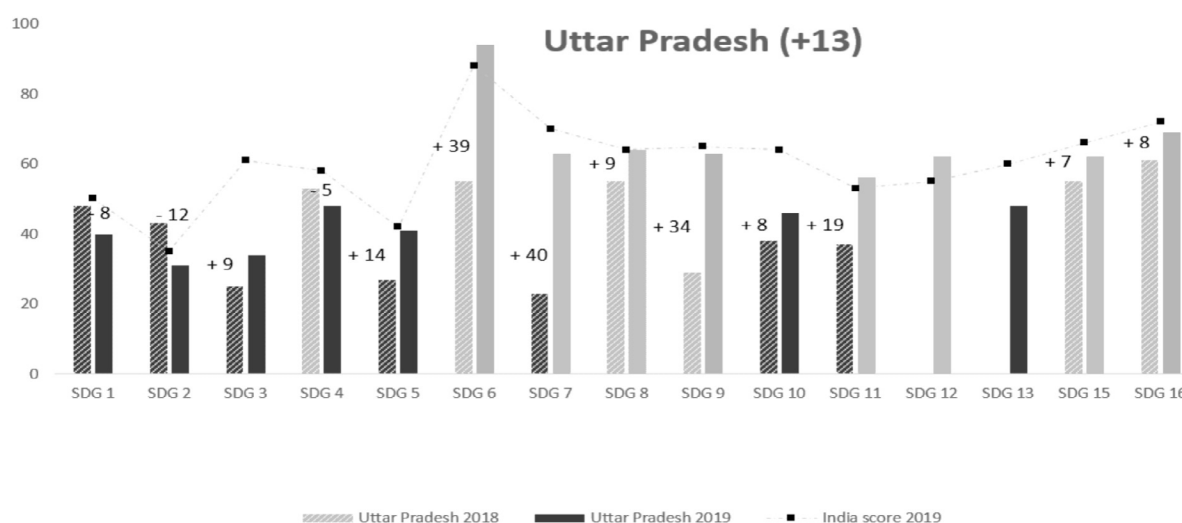
Union Territories	2018 Rank	2019 Rank	Direction of change
Chandigarh	1	1	▲
Puducherry	2	2	▲
Daman & Diu	3	5	▼
Delhi	4	5	▼
Lakshadweep	4	3	▲
Andaman & Nicobar Islands	6	5	▲
Dadra & Nagar Haveli	7	3	▲
Jammu & Kashmir and Ladakh	20	8	▼

7: 2018 तथा 2019 में संघ राज्य क्षेत्र तथा रैंक

तीव्रतम प्रवर्तक:

- वर्ष 2018 का सबसे बड़ा सुधार उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्कोर में 13 अंकों की वृद्धि और 29 वीं से 23 वीं रैंक के उछाल के साथ प्राप्त किया गया था।
- ओडिशा और सिक्किम 7 अंकों के उछाल के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
- ओडिशा 23 वें स्थान से 15 वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि सिक्किम राज्य का 15 वीं से 7 वीं रैंक में सुधार हुआ।
- इन क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी स्कीमों तथा कार्यक्रमों की सफलता के कारण इन राज्यों ने एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), 9 (उद्योग, नवोन्मेष और बुनियादी ढांचे) में सराहनीय प्रगति की है।

चित्र 6: 2018 तथा 2019 में राज्य तथा रैंक



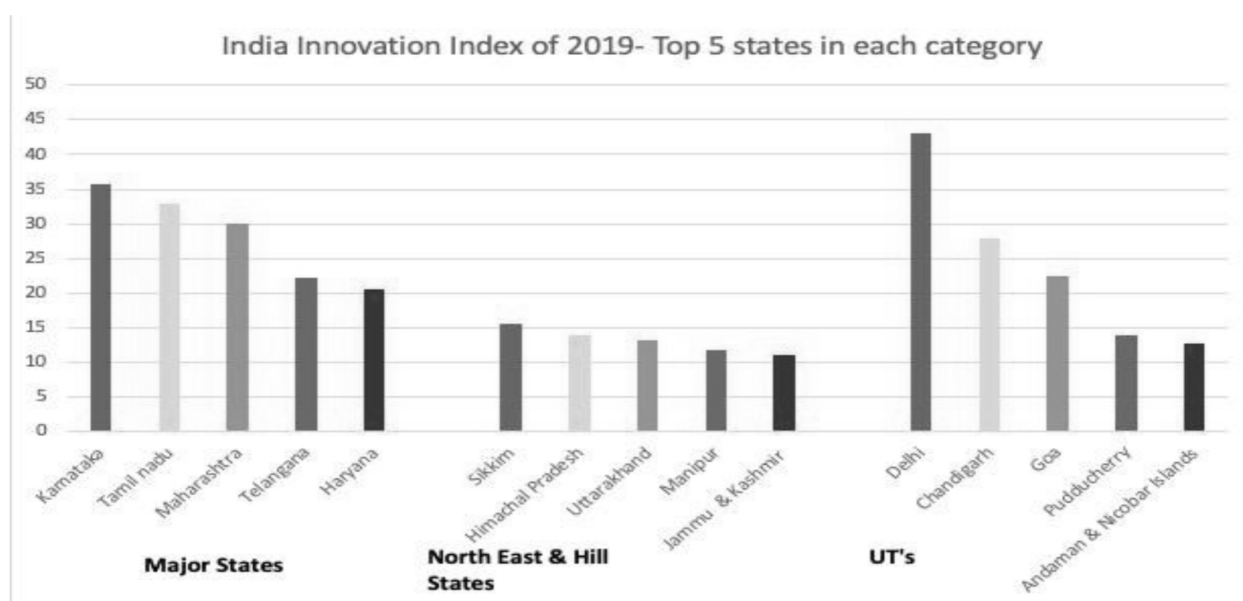
चित्र 8: उत्तर प्रदेश के लिए 2018 से 2019 तक तीव्रतम प्रवर्तक के रूप में लक्ष्य-वार परिवर्तन

व्यक्तिगत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की रूपरेखा

- रैंकिंग के अलावा, 2019 संस्करण में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की रूपरेखा संबंधी एक खंड भी है, जो उनसे संबंधित निष्पादन और संकेतक मूल्यां पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रगति को चिह्नित करने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को साझा करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण को प्रोत्साहित करेगा।

भारत नवोन्मेष सूचकांक

- भारत के लिए विकास और समृद्धि के प्रमुख संचालक के रूप में नवोन्मेष की भूमिका को स्वीकार करते हुए, नीति आयोग ने 17 अक्टूबर, 2019 को भारत नवोन्मेष सूचकांक जारी किया। सूचकांक 29 राज्यों और सात संघ राज्य क्षेत्रों के नवोन्मेष पर्यावरण के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रूपरेखा बनाता है तथा उनके सूचकांक स्कोर के आधार पर उनका स्थान निर्धारित करता है।
- देश भर के नीति निर्धारक अपने क्षेत्रों की आर्थिक विकास नीतियों को तैयार करते समय, सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए सूचकांक और क्षमता निर्माण का उपयोग कर सकते हैं।

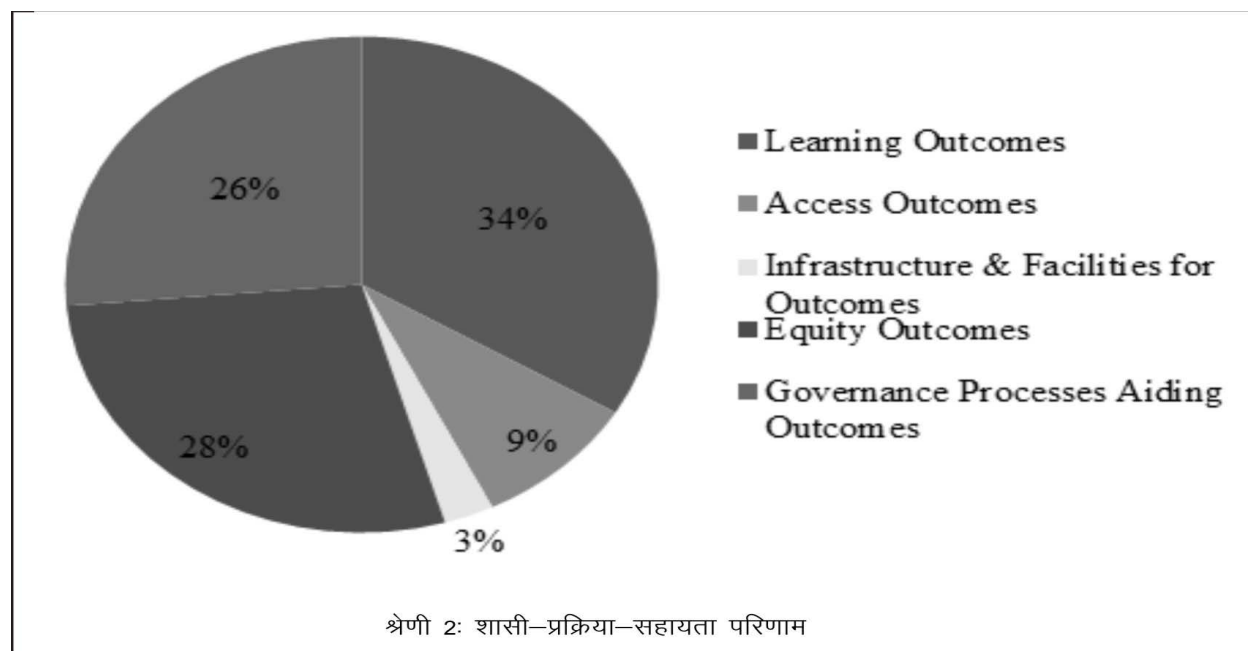


स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

- स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) विकसित किया गया था।
- इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने तथा अपेक्षित पाठ्यक्रम सुधार करने अथवा नीतिगत कार्यक्रमों का एक मंच उपलब्ध कराकर शिक्षा नीति हेतु 'परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना है।
- प्रतिस्पर्धी और सहयोगी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अधिदेश के अनुरूप, एसईक्यूआई देश भर में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), विश्व बैंक और क्षेत्र विशेषज्ञों जैसे प्रमुख हितधारकों सहित एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित सूचकांक में 30 महत्वपूर्ण संकेतक शामिल हैं।
- स्कूली शिक्षा के परिणाम वास्तविक शिक्षण परिणामों में होने चाहिए। यह प्रणाली शिक्षण सीखने की ओर अग्रसर है यह सुनिश्चित करने के लिए एसईक्यूआई शिक्षण परिणामों के लिए लगभग अपना आधा योगदान देता है।
- शिक्षण पर ध्यान केंद्रित रहे यह सुनिश्चित करने के लिए यह समूचे राष्ट्र में एक मजबूत संकेत भेजता है।
- तुलनात्मक सुविधा प्रदान करने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- इन समूहों में समग्र निष्पादन स्कोर तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए रैंकिंग का सृजन करने हेतु संकेतक मूल्यों को उचित रूप से बढ़ाया, मानकीकृत और मापा गया है।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित वर्ष 2016-17 में उनके समग्र निष्पादन के साथ-साथ संबंधित वर्ष और बुनियादी वर्ष (2015-16) के बीच उनके निष्पादन में बदलाव के अनुसार रैंक दिया जाता है।
- यह रैंकिंग, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की स्थिति तथा समय के साथ उनकी सापेक्ष प्रगति में अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है।
- इस वर्ष के दौरान, नीति आयोग ने सभी संकेतकों के लिए आंकड़े संचयन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट के प्रथम संस्करण को 30 सितंबर, 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। केरल, मणिपुर और चंडीगढ़ समग्र प्रदर्शन में शीर्ष पर रहे जबकि हरियाणा, मेघालय, दमन और दीव ने सबसे अधिक सुधार दिखाया।



Overall Performance Ranking				Incremental Performance Ranking			
Large States		Small States		Large States		Small States	
Rank	State	Rank	State	Rank	State	Rank	State
1	Kerala	1	Manipur	1	Haryana	1	Meghalaya
2	Rajasthan	2	Tripura	2	Assam	2	Nagaland
3	Karnataka	3	Goa	3	Uttar Pradesh	3	Goa
Union Territories				Union Territories			
Rank	Union Territory	Rank	Union Territory	Rank	Union Territory	Rank	Union Territory
1	Chandigarh			1	Daman & Diu		
2	Dadra & Nagar Haveli			2	Dadra & Nagar Haveli		
3	Delhi			3	Puducherry		

शीर्ष प्रदर्शनकारी दृष्टि एसईक्यूआई समग्र प्रदर्शन रैंकिंग

शीर्ष प्रदर्शनकारी - एसईक्यूआई वर्धित प्रदर्शन रैंकिंग

जल प्रबंधन सूचकांक

- संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक का दूसरा दौर जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत तथा नीति आयोग उपाध्यक्ष, डॉ जीव कुमार द्वारा 14 अगस्त 2019 को आरंभ किया गया था। इसे सभी राज्यों में परिचालित किया गया है।
- इस प्रयास से राज्यों में पानी के उपयोग के विभिन्न पहलुओं में आंकड़े अनुरक्षण तथा जल संरक्षण की भावना पैदा हो सकती है। यह एक वार्षिक कार्य है, सूचकांक के तीसरे दौर का कार्य आरंभ हो चुका है।

सहयोगी संघवाद

1. पांचवीं शासी परिषद की बैठक

परिचय

- नीति आयोग का गठन एक मजबूत राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु सहयोगी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने और भारत में सुशासन को सक्षम करने के लिए किया गया है।
- सहयोगी संघवाद की दो प्रमुख विशेषताएं हैं
 - केंद्र तथा राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा पर संयुक्त फोकस और
 - केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की चिंताओं और मुद्दों पक्षपोषण।
- नीति आयोग ने अवसररचना विकास के लिए मॉडल और कार्यक्रम भी स्थापित किए हैं।
- इसके अलावा, क्षेत्रीय विकासात्मक असंतुलन को ठीक करने के उद्देश्य से, नीति आयोग ने पूर्वोत्तर, द्वीप और हिमालयी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने और सहायता की आवश्यकता को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नीति ने विशेष नीतियां बनाने के लिए विशेष मंचों का गठन किया है।

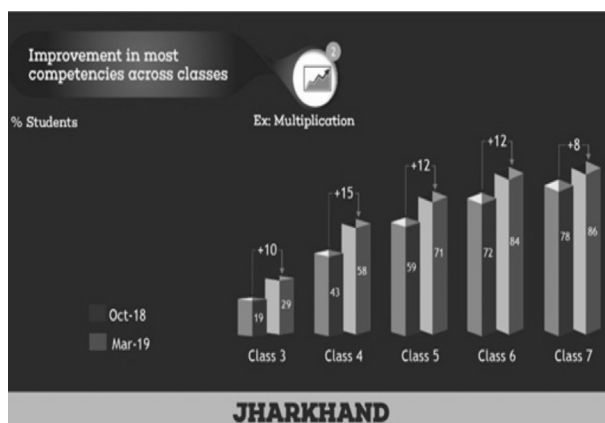
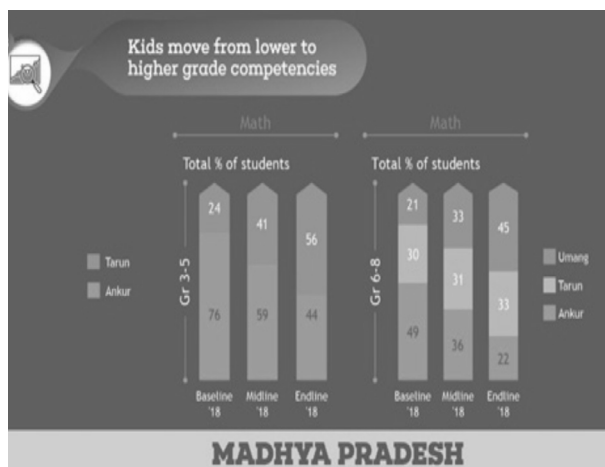
शासी परिषद

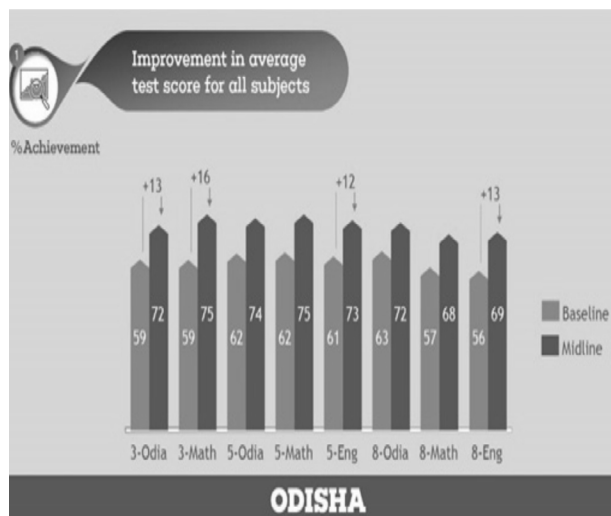
- नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
- इसका गठन 16 फरवरी 2015 को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से हुआ।

शिक्षा में मानव पूंजी परिवर्तन हेतु संधारणीय कार्रवाई (एसएटीएच)

- मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को व्यवस्थित रूप से सुधारना और परिवर्तन के मॉडल राज्य बनाना है।
- सितंबर 2017 में शुरू की गई परियोजना के लिए चुनौती पद्धति पर आधारित तीन राज्यों- झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा को चुना गया था।

- इस कार्यक्रम को ज्ञान भागीदारों बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और शिक्षा नेतृत्व के लिए पीरामल फाउंडेशन (पीएफईएल) संघ और इस प्रक्रिया में सुविधा प्रदाता और समन्वयक के रूप में नीति आयोग के साथ इन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना के तीसरे चरण का कार्य चल रहा है और मार्च 2020 में पूरा होने की संभावना है।
- अकादमिक और प्रशासनिक सुधार को सुविधाजनक बनाने वाले कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं:
 - बड़े पैमाने पर सीखने के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना
 - स्कूल विलय और समेकन
 - शिक्षक भर्ती और युक्तिकरण
 - प्रणाली-व्यापी प्रशिक्षण और निगरानी कार्यक्रम
 - प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को मजबूत बनाना
 - जिलेवार स्कोरकार्ड के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
 - स्कूल प्रमाणन कार्यक्रम





अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (डीएसएसएस) हेतु विकास सहायता सेवाएं

- अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (डीएसएसएस) हेतु विकास सहायता सेवाओं का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सफलता की कहानियां बनाना और अवसंरचना परियोजना के वितरण मॉडल को रिबूट करना है ताकि एक स्थायी अवसंरचना निर्माण चक्र स्थापित हो सके।
- इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अवधारणा योजना से लेकर वित्तीय समापन तक की परियोजना-स्तरीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
- नीति आयोग ने चयनित अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करने के लिए लेनदेन-प्रबंधन सहायता प्रदान करने हेतु बाहरी सलाहकारों को शामिल किया है।
- रणनीतिक योजना विकसित करने और विशेष रूप से पर्यटन, सौर ऊर्जा और अन्य के लिए सहायता प्रदान करने के लिए नवगठित केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत पूरा किया जाना है।

पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच

- पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच का गठन फरवरी 2018 में किया गया था, ताकि हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित, समावेशी लेकिन सतत आर्थिक विकास के लिए विभिन्न बाधाओं की पहचान की जा सके।
- यह नीति आयोग द्वारा गठित पहला क्षेत्रीय मंच है। इस मंच की सह-अध्यक्षता उपाध्यक्ष, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री द्वारा की जाती है।

- पहली बैठक 10 अप्रैल 2018 को अगरतला, त्रिपुरा में हुई थी।
- पांच प्रमुख जोर देने वाले क्षेत्रों जैसे पर्यटन, चाय, बांस, डेयरी और मत्स्यपालन की पहचान की गई है और पांच समानांतर सत्रों में इन पर चर्चा की गई।
- मिजोरम और सिक्किम में केबल कार के बहु-मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता अध्ययन के प्रस्तावों का मूल्यांकन, केंद्र और राज्य सरकारों के समर्थन से कार्यान्वित किया जाना है।

बांस क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत पहल:

- मिजोरम सरकार ने स्थायी कृषि और ग्रामीण आजीविका परिवर्तन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए बांस क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सुबनसिरी परियोजना:

- सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना का कार्य जारी है और संबंधित अधिकारियों के साथ इसका नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है।
- इसके परिणामस्वरूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अनुवर्ती मंजूरी के बाद, असम सरकार ने नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एनएचपीसी के साथ एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सिवोक-रंगपो रेल परियोजना और अगरतला अखौरा रेल परियोजना:

- राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को सिवोक-रंगपो रेल परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- अगरतला-अखौरा रेल परियोजना पर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, हाल ही में भारत की ओर से इस परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई थी।

द्वीपों का समग्र विकास

समग्र विकास के लिए द्वीपों की पहचान करना

10 द्वीपों नामतः:

- अंडमान और निकोबार में एविस, लागु, लिटिल अंडमान, स्मिथ और लक्षद्वीप में बांगाराम, चेरियाम, मिनिर्कोय, सुहेली और टिन्नाकरा को संधारणीय विकास के लिए निर्दिष्ट किया गया।
- इस संबंध में, नीति आयोग द्वारा अवधारणा विकास योजनाओं और नौ द्वीपों के विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार में चार (एविस, लांग, स्मिथ, और रॉस) और लक्षद्वीप में पाँच (बांगरम, चेरियाम, मिनिर्कोय, सुहेली और तिन्नकारा) स्थानों पर एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

- ☉ इन द्वीपों के लिए अंतिम मास्टर प्लान और बुनियादी ढांचा योजना तैयार की गई है। इन द्वीपों की वहन क्षमता निर्धारित की गई है और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय क्षेत्रीकरण किया गया है।
- ☉ हवाई संपर्क में सुधार हेतु, नागरिक विमानों के लिए डिगलीपुर हवाई अड्डे को चालू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।
- ☉ मिनिक्ॉय में हवाई अड्डे का निर्माण, जो हमारे देश के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, भारतीय वायु सेना (आईएफ) को सौंपा गया है।

विकास के लिए अतिरिक्त द्वीपों की पहचान

- ☉ नीति आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के परामर्श से, सतत विकास के लिए 17 और द्वीप/स्थलों (अंडमान और निकोबार में 12 और लक्षद्वीप में पांच) की पहचान की है।
- ☉ ये हैं- अंडमान और निकोबार में नॉर्थ पैसेज, सिनक, इंगलिस, वाइपर, नील (भरतपुर बीच), रामनगर बीच, करमटांग बीच, धनीनाला बीच, कालीपुर बीच, रटलैंड, नॉर्थ बे और ग्रेट निकोबार (बी क्वारी) हैं तथा लक्षद्वीप में कलपनी, कदमत, अगात्ती, चेतलत और बिट्टा।
- ☉ इन अतिरिक्त द्वीपों के समग्र विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं।

लक्षद्वीप में चिन्हित द्वीपों के विकास के लिए भूमि संबंधी मामले:

- ☉ 24 अप्रैल 2018 को आयोजित द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की तीसरी बैठक की सिफारिश के आधार पर, डॉ. टी. हक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
- ☉ समिति से अनुरोध किया गया था कि वह लक्षद्वीप (मिनिक्ॉय, सुहेली, बांगरम, चेरियम और थिनककारा द्वीप) के चिन्हित द्वीपों में भूमि संबंधी मामलों के समाधान के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव मॉडल की सिफारिश करें।

लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के समग्र विकास के लिए समिति की रिपोर्ट

- ☉ लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के समग्र विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।
- ☉ समिति ने व्यापक विचार-विमर्श किया, क्षेत्र का दौरा किया और दोनों द्वीपों में स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मतभिन्नता

- ☉ भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खारे पानी वाले मगरमच्छों के संदर्भ में मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जल संसाधनों का विकास

- ☉ वापकोस (जल एवं विद्युत कंसल्टेंसी सर्विसेज) को लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जल संसाधनों के विकास हेतु एक शोध अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संधारणीय विकास

- ☉ भारतीय हिमालयी क्षेत्र, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है अर्थात्, यह 11 राज्यों-उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में फैला है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फैला हुआ है, जहां लगभग 50 मिलियन लोग निवास करते हैं।
- ☉ यह क्षेत्र विविध जनसांख्यिकीय और विविध आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों द्वारा अभिलक्षित है।
- ☉ वर्ष 2017 में, निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पाँच कार्यदलों का गठन किया:
 - i) जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की स्थिति और पुनरुद्धार,
 - ii) भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संधारणीय पर्यटन,
 - iii) स्थानान्तरण कृषि, परिवर्तनशील दृष्टिकोण की ओर,
 - iv) हिमालय में कौशल और उद्यमिता (ई एंड एस) परिदृश्य को सुदृढ़ करना
 - v) सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा/सूचना।
- ☉ जल सुरक्षा के लिए हिमालयी क्षेत्र में इन्वेंटरी एंड रिवाइवल ऑफ स्प्रिंग्स की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय ने स्प्रिंग्स के कार्याकल्प पर एक रूपरेखा प्रस्तुत किया।
- ☉ रिपोर्ट में कार्रवाई हेतु रोडमैप में की गई सामान्य सिफारिशों के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण और सतत विकास संस्थान और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, काठमांडू ने इस क्षेत्र में विज्ञान-नीति-अभ्यास विभाजन को बढ़ावा देने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए, हिमालय कॉलिंगर नामक एक पहल शुरू की है।

थिंक टैंक की गतिविधियाँ

1. ज्ञान का दायरा बढ़ाना फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को अपनाते एआई स्ट्रेटेजी दस्तावेज

परिचय

- नीति आयोग ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस साल कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है।
- इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना और 5 अक्टूबर 2019 को असम में भारत के पहले मेथनॉल आधारित खाना पकाने के स्टोव को प्रज्वलित करना शामिल है।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले टैंकों, शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों और विषय विशेषज्ञों के साथ व्यापक रूप से संलग्न होने के कारण प्रमुख हितधारकों के बीच साझेदारी का विकास हुआ है।

ज्ञान का बढ़ता दायरा

I- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संबंधी राष्ट्रीय रणनीति

- 2018-19 के बजट में भारत सरकार ने हमारी प्रौद्योगिकी क्षमताओं का निर्माण करने को प्राथमिकता दी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को निर्देशित करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए नीति आयोग को अधिदेश दिया।
- नीति आयोग ने जून 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एनएसएआई) के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति जारी की।
- यह रणनीति, नामतः सभी के लिए एआई, सामाजिक विकास और समावेशी विकास के साथ एआई की आर्थिक क्षमता को जोड़ती है, और भारत को दुनिया का एआई के रूप में स्थान देती है।
- इसके साथ, भारत एक अच्छी तरह से परिभाषित एआई रणनीति वाले देशों की कुलीन सूची में शामिल हो गया है।
- नीति आयोग इस रणनीति की सिफारिशों को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र और निवेश ढांचे को औपचारिक बनाने की प्रक्रिया में है।
- एनएसएआई पांच विशिष्ट सिफारिशों के माध्यम से भारत की अनुसंधान और अनुप्रयोग क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है।
 - i- मूलः शीर्ष-स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में पांच केंद्रों के माध्यम से एआई में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करना।
 - ii- आईसीटीएआई: एआई समाधान पर ध्यान केंद्रित करने

के लिए उद्योग के साथ मिलकर एआई में परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र।

- iii- एआईआरएडब्ल्यूएटी: छात्रों, शोधकर्ताओं, स्टार्ट-अप और सरकारी संगठनों के लिए एआई विशिष्ट कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर क्लाउड-आधारित एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना तथा उच्च भंडारण के लिए अनुकूलित 100 पेटाफ्लॉप्स।
- iv- मूनशॉट परियोजनाएं: महत्वाकांक्षी एआई चुनौतियां तकनीक को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
- v- एकरूपता हेतु एआई: एक बहु-विषयक, बहु-राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी सीमा को और एआई के आवेदन का लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात् आवश्यक संसाधनों, स्वच्छता, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और सेवाओं की वहीनीयता और उपलब्धता के स्वतंत्र व्हीकलों से अभिगम समाधान द्वारा बदलाव करना।

- सिफारिशों का उद्देश्य दुनिया भर से भारत में एआई अनुसंधान प्रतिभाओं को आकर्षित करना है।
- भारत में एआई के अंतर्गत गुणवत्ता अनुसंधान संकाय की कमी को देखते हुए, कम समय में एक उपयुक्त प्रोत्साहन तंत्र (जो शीर्ष स्तर की बुनियादी सुविधाओं से युक्त हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर का पारिश्रमिक देय हो) की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, इस क्षेत्र में भारतीय पीएचडी विद्वानों, जो अन्यथा विदेशों में शीर्ष विश्वविद्यालयों से अपनी पढ़ाई करते हैं, को एक उपयुक्त प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से देश में बरकरार रखने की आवश्यकता है।

II- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी पायलट परियोजनाएं

- आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी, बैंगलोर, टाटा मेमोरियल अस्पताल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर कैंसर परियोजना के लिए इमेजिंग बायोबैंक का विकास करना।
- इस परियोजना का उद्देश्य 20,000 से अधिक कैंसर रोगियों से संबंधित रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी छवियों के एक डेटाबेस का निर्माण करना है, जो भारत में प्रचलित कैंसर के प्रमुख प्रकारों पर ध्यान देने के साथ-साथ नैदानिक आंकड़ों से संबंधित एक टीका है।
- डेटाबेस की परिकल्पना एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में की गई है जो भारत के सभी हिस्सों के शोधकर्ताओं के लिए खुला रहेगा और इसका उद्देश्य कैंसर रोगियों की पूरी अधोमुखी प्रोफाइल विकसित करना है।
- भारत-यूके हेल्थकेयर एआई उत्प्रेरक परियोजना: नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, यूके के साथ मिलकर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, आंख की स्थिति, महिलाओं और बच्चों

के स्वास्थ्य और रक्त रोग, जैसे थैलेसीमिया जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित परीक्षण और कार्यान्वित तकनीकी समाधान लाने के लिए कार्यरत है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टेक: रणनीतिक और दृष्टिकोण परामर्श दस्तावेज

- नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टेक (एनएचएस) के लिए एक रूपरेखा को लागू करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे के रूप में तैयार किया गया है।
- अक्टूबर 2019 में जारी, यह ब्लूप्रिंट राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की दृष्टि के साथ संरेखित है। यह एक ऐसा ढांचा है जो भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों की शक्ति का उपयोग करता है।
- यह बड़ा सोचो, छोटा शुरू करो, जल्दी शुरू करो के सिद्धांत को अपनाता है और नागरिक-केंद्रित, गुणवत्ता देखभाल, बेहतर पहुंच, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और समावेश के लिए आधार बनाता है।
- यह स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा अनुप्रयोगों और डेटा के एकीकरण के लिए एक साझा मंच प्रदान करने में मदद करेगा। यह डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की ओर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लिए रणनीति

- कच्चे तेल के आयात को कम करने और देश के कार्बन पद्वि को हटाने व स्वदेशी ईंधन विकसित करने की महत्वाकांक्षा के साथ, नीति आयोग मेथनॉल और डाइमेथिल ईथर (डीएमई) से युक्त तेल और प्राकृतिक गैस के संभावित विकल्प के रूप में काम कर रहा है।
- नीति आयोग के सदस्य (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में गठित एक शीर्ष समिति, देश में मेथनॉल अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।
- यह कोयले के अलावा उच्च राख कोयला, बायोमास नगरपालिका ठोस अपशिष्ट/स्रोतों का उपयोग करके मेथनॉल के उत्पादन पर गठित कार्यक्षेत्रों की गतिविधियों की प्रगति पर भी नजर रखता है।
- यह मेथनॉल-आधारित इंजनों के रूपांतरण/डिजाइन का उपयोग करता है और मेथनॉल डीएमई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना का प्रसार करता है।
- उक्त पहलों के अंतर्गत गतिविधियों की स्थिति निम्नानुसार है:
 1. राख के कोयले का उपयोग करके मेथनॉल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने संबंधी आर

एंड डी परियोजना, पूर्ण होने वाली है और शीघ्र ही एक टन प्रतिदिन मेथनॉल-उत्पादन क्षमता संयंत्र का प्रदर्शन किया जाएगा।

2. बायोमास के उपयोग से मेथनॉल के उत्पादन संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (आर एंड डी परियोजनाएं), अच्छा कार्य कर रही हैं। परियोजना का पहला चरण भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर द्वारा पूरा किया गया है।
3. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को एम15, एम 85 और एम100 मेथनॉल में क्रमशः पेट्रोल, 15%, 85% और 100% की मात्रा मिश्रित करने के बारे में सूचित किया गया है।
4. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एम15 के लिए भारतीय मानक तैयार किया गया है।
5. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने एम15 मिश्रण तैयार किया है और इसकी स्थिरता की जाँच की गई है।
6. आईओसी द्वारा किए गए शोध कार्य से पता चला है कि पेट्रोल में 15% मेथनॉल और एलपीजी में 20% डीएमई का मिश्रण, आंतरिक दहन इंजनों में, या उपकरण : हिस्सों में किसी विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं थी।
7. एम 15 मिश्रण के लिए उत्सर्जन और सामग्री अनुकूलता, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे द्वारा पूरी की गई है।
8. एआरएआई ने, मारुति सुजुकी के साथ मिलकर, सड़क परीक्षण और एम15 पर वाहनों के स्थायित्व परीक्षण को पूरा कर लिया है।
9. आईओसी ने एम 15-मिश्रित पेट्रोल पर प्रदर्शन और उत्सर्जन परीक्षण किया है।
10. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा, 100% मेथनॉल पर काम करने के लिए एक वर्कबोट के रूपांतरण पर कार्य प्रगति पर है।
11. असम पेट्रोकेमिकल्स के सहयोग से, असम सरकार ने मेथनॉल आधारित खाना पकाने के स्टोव शुरू किए हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं।
12. एआरएआई, पुणे में एक मेथनॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एमओआरटीएच और भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण किया गया है।
13. एमओआरटीएच ने अपने मौजूदा ईंधन वितरण नेटवर्क के माध्यम से वितरण के लिए ईंधन के रूप में एम15 को अपनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पत्र लिखा है।

14. वैकल्पिक ईंधन के रूप में मेथनॉल के उपयोग संबंधी व्यय वित्त समिति को भेजे जाने वाला ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।

रणनीतिक वार्ता

छठा भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता 2019

- ❶ एसईडी के तत्वावधान में, दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधि रचनात्मक रूप से विचार-विमर्श करने और व्यक्तिगत सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, आसानी से व्यापार करने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सेक्टर-विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों की सफलतापूर्वक पहचान करने के लिए एक साथ आए हैं।
- ❷ दोनों पक्षों द्वारा सह-अध्यक्षों (संयुक्त सचिव के पद से ऊपर) के साथ छह स्थायी संयुक्त कार्य समूह को बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उच्च तकनीक, संसाधन संरक्षण, फार्मास्यूटिकल्स और नीति समन्वय के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों को पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया है, ताकि नियमित संवाद और निरंतर विनिमय सुनिश्चित हो सके।

छह कार्य समूहों के व्यावहारिक और परिणाम-उन्मुख विचार-विमर्श के बाद के आपसी समझौतें:

नीति समन्वय:

- ❶ दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश की समीक्षा के लिए गहन विचार-विमर्श किया, ताकि इस प्रभाव के पूरक और बेहतर समन्वय की पहचान की जा सके।
- ❷ फिनटेक और संबंधित तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवाचार और निवेश में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया।
- ❸ दोनों पक्ष संचार के नियमित माध्यम को और सक्रिय करने के लिए गतिविधियों से युक्त वार्षिक कैलेंडर का आदान-प्रदान करने पर सहमत हुए।
- ❹ अवसंरचना संबंधी कार्य समूह: दोनों पक्षों ने चेन्नई-बेंगलुरु-मैसूरु रेलवे-उन्नयन परियोजना और चीन में भारतीय वरिष्ठ रेलवे प्रबंधन कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर व्यवहार्यता अध्ययन में उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख किया।
- ❺ उन्होंने पायलट परियोजना के रूप में दिल्ली-आगरा हाई-स्पीड रेलवे की संभावना तलाशने वाले अध्ययन परियोजना को आगे बढ़ाने के साथ-साथ समन्वय के सभी क्षेत्रों में अगले चरणों की पहचान करने पर विस्तृत चर्चा की।
- ❻ दोनों पक्ष परिवहन क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए नई परियोजनाओं की पहचान करने पर भी सहमत हुए।

उच्च तकनीकी संबंधी कार्य समूह:

- दोनों पक्षों ने पांचवें एसईडी के बाद से हासिल की गई उपलब्धियों का आकलन किया और व्यापार आसान करने की नियामक प्रक्रियाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, उच्च तकनीकी निर्माण और दोनों देशों की अगली पीढ़ी की मोबाइल संचार व्यवस्था पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- साथ ही, तकनीकी नवाचार, औद्योगिक स्थिति, और तंत्र के साथ-साथ भारत-चीन डिजिटल साझेदारी, डेटा शासन और संबंधित उद्योग नीति को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।
- संसाधन संरक्षण और पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्य समूह: दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण और उजाड़ अपशिष्ट व संसाधन संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा और समीक्षा की।
- इस क्षेत्र में नवाचार की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया। कम लागत वाली निर्माण तकनीकी, बाढ़ और कटाव नियंत्रण पद्धति, वायु प्रदूषण, आदि में उपयोगी अवधारणाओं के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई।
- दोनों पक्षों ने उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जैसे कि बिजली की बर्बादी, सीवेज कीचड़ के साथ सह-प्रसंस्करण, तूफान जल प्रबंधन, आदि।
- उपरोक्त क्षेत्रों में उन्नत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, दोनों पक्ष निरंतर संपर्क और प्रासंगिक जानकारी के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।
- ऊर्जा संबंधी कार्य समूह: दोनों देशों ने समन्वय के भविष्य के क्षेत्रों की पहचान की और अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, स्मार्ट ग्रिड और ग्रिड एकीकरण तथा स्मार्ट मीटर व ई-गतिशीलता पर काम करने का संकल्प लिया।
- उन्होंने वैकल्पिक सामग्री से सौर सेल के निर्माण के लिए नई तकनीक विकसित करने और सौर कोशिकाओं की दक्षता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास में सहयोग पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों पक्ष ई-गतिशीलता और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में समन्वय पर भी सहमत हुए।

फार्मास्यूटिकल्स संबंधी कार्य समूह:

- ❶ संयुक्त कार्य समूहों ने उल्लेख किया है कि दोनों पक्षों को व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संचार को और अधिक मजबूत करना चाहिए।

- ☛ यह भी तय किया गया कि दोनों पक्षों को दवा उद्योग में पूरक लाभ को मजबूत करना चाहिए और भारतीय जेनेरिक दवाओं तथा चीनी एपीआई को बढ़ावा देना चाहिए।
- ☛ दोनों पक्षों ने उत्कृष्ट मामलों और समन्वय के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक अतिमहत्वपूर्ण और स्थायी साधन के रूप में एसईडी तंत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की।

3. सतत विकास संबंधी यूएन ईएससीएपी एशिया-पेसिफिक मंच

- ☛ भारत ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार के नेतृत्व में 27-29 मार्च 2019 तक बैंकाक में सतत विकास पर छठे एशिया-प्रशांत फोरम में भाग लिया।
- ☛ इसमें सदस्य राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्र निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों ने विचार-विमर्श पर आधारित विषय 'लोगों को सशक्त बनाना और समावेशी व समानता सुनिश्चित करना' पर चर्चा की।
- ☛ यह सात एसडीजी समूह की स्थिति की समीक्षा करता है: 4 (गुणवत्ता शिक्षा), 8 (सभ्य काम और आर्थिक विकास), 10 (असमानताओं में कमी करना), 13 (जलवायु कार्रवाई), 16 (शांति, न्याय 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी)।

सतत विकास संबंधी उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच

- ☛ 2019 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान में आयोजित सतत विकास संबंधी उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की बैठक 9 से 18 जुलाई 2019 तक आयोजित की गई।
- ☛ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने किया था और इसमें संयुक्ता समददार, परामर्शदाता, नीति आयोग भी शामिल थीं।

नीति आयोग लेक्चर श्रृंखला

- ☛ भारत में विकास की नीति में नवीन विचारों के प्रसार हेतु, नीति लेक्चर में सरकार के शीर्ष निर्णय निर्माताओं, मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्रालयों व विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित भाग लेते हैं।
- ☛ लेक्चर के माध्यम से, नीति आयोग भारत में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और वैश्विक ख्याति के प्रशासकों को आमंत्रित करता है।
- ☛ श्रृंखला का उद्देश्य सफल विकास अभ्यास के आधार पर केंद्र और राज्यों दोनों स्तर पर सीखने की क्षमता को सक्षम बनाना है।

अर्थशास्त्रियों की बैठक

- ☛ नीति आयोग ने 9 जनवरी, 2020 को विभिन्न वरिष्ठ

अर्थशास्त्रियों, निजी इक्विटी और उद्यम पूंजीपतियों, विनिर्माण, यात्रा और पर्यटन, परिधान और एमएमसीजी, एनालिटिक्स, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वित्त क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की।

- ☛ प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और भारत में 5 ट्रिलियन यूएसडी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
- ☛ पर्यटन, शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और कृषि आधारित उद्योग जैसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और रोजगार पैदा करने की काफी संभावना है। हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और राष्ट्र की तरह सोचना शुरू करना चाहिए।

एनआईएलआईआरडी

- ☛ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एनआईएलआईआरडी) नीति आयोग, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
- ☛ इस संस्था के प्राथमिक उद्देश्य मानव पूंजी नियोजन, मानव संसाधन विकास, निगरानी और मूल्यांकन के सभी पहलुओं में अनुसंधान, डेटा संग्रह और शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं।

संस्थान द्वारा संचालित की जा रही पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम

- ☛ वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) (14 मार्च -24 अप्रैल 2019)
 - भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव संसाधन क्षेत्र में प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ प्रतिभागियों की पहचान करना है।
 - जिसमें रोजगार कानून, नौकरी विश्लेषण, नियोजन, भर्ती और चयन, प्रशिक्षण और विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन, मुआवजा, औद्योगिक संबंध, वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन, आदि शामिल हैं।

नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना

अटल नवप्रवर्तन मिशन

- ☛ अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है।
- ☛ एआईएम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करना विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए जागरूकता और एक छत्र संरचना का निर्माण करना है।

एआईएम द्वारा की गई छह प्रमुख पहल

- अटल टिकरिंग लैब्स: भारत के समस्त स्कूलों की समस्या को सुलझाने हेतु माहौल का निर्माण करना।
- अटल ऊष्मायन केंद्र: विश्व स्तर के स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना और इनक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ना।
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज: उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।
- मेंटर इंडिया कैपेन: मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट और संस्थानों के सहयोग से एक राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क बनाना।
- अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर: टियर -2 और टियर -3 शहरों सहित देश के अनछुए क्षेत्रों में सामुदायिक-केंद्रित नवाचार और विचारों को प्रोत्साहित करना।
- उन्नयन: एमएसएमई उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

एआईएम की गत वर्ष की गतिविधियां:**स्कूल स्तर पर अटल टिकरिंग लैब्स**

- पिछले दो वर्षों में, एआईएम ने हजारों अटल टिकरिंग लैब्स की स्थापना की है, इस प्रकार ग्रेड 6 से 12 तक के छात्रों को 3 डी प्रिंटर, रोबोटिक्स, और लघु इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नवीन उपकरणों और तकनीकों के साथ एक्सेस करने और टिकर करने में मदद मिलती है।

विश्वविद्यालय, संस्थान और उद्योग स्तर पर अटल इंक्यूबेटर

- एआईएम स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉरपोरेट्स आदि में अटल इंक्यूबेशन सेंटर नामक विश्व स्तरीय इनक्यूबेटर स्थापित कर रहा है।
- आज तक एआईएम ने इन इनक्यूबेटरों को स्थापित करने के लिए 102 विश्वविद्यालयों, संस्थानों और निजी संगठनों का चयन किया है, इनमें से हर कोई प्रत्येक चार वर्षों में 40-50 विश्व स्तरीय स्टार्ट-अप के निर्माण और पोषण को बढ़ावा देगा।
- एआईसी की परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और कुशल नेतृत्व, सहयोग और साझेदारी के सक्रिय विकास और नई पहल से किया जा रहा है।

- अटल कम्युनिटी इनोवेशन केंद्र- भारत के अनछुए क्षेत्र टियर -2 और टियर -3 शहरों, आकांक्षी जिलों, आदिवासी, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों सहित भारत के अनछुए क्षेत्रों में तकनीक वाले नवाचार के लाभों को बढ़ावा देने के लिए, ओआईएम अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित कर रहा है।
- इन केंद्रों में एक विशेष साझेदारी-संचालित मॉडल है, जहां एआईएम एसीआईसी को 2.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान देता है, बशर्ते कि भागीदार एक समान या उससे अधिक राशि प्रदान करता हो।
- एसीआईसी की परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और कुशल नेतृत्व, सहयोग और साझेदारी के सक्रिय विकास और नई पहल से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:
 - एसीआईसी एप्लीकेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज- राष्ट्रीय हितों के साथ उत्पाद और सेवा नवाचार

- राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाले उत्पाद और सेवा नवाचार बनाने के लिए, एआईएम ने केंद्र सरकार के पांच अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के साथ साझेदारी करके 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है।

एमएसएमई इंडस्ट्री इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु एप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज

- एमएसएमई/स्टार्ट-अप क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, एआईएम, साथी मंत्रालयों के साथ एआरआईएसई (एप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज) शुरू करेगा, ताकि उत्पाद विकास और वाणिज्यिक तैनाती करते हुए महान अनुसंधान विचारों को व्यवहार्य अभिनव प्रोटोटाइप में परिवर्तित किया जा सके।

सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, संस्थानों के साथ मेंटरशिप और भागीदारी

- सभी पहलों को सफल बनाने के लिए, एआईएम ने श्मेंटर इंडियारू द मेंटर ऑफ चेंज श्नामक एक सबसे बड़ा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है।
- आज तक, एआईएम को नोनेट पोर्टल पर 10000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4000 से अधिक को एटीएल और एआईली को आवंटित किया गया है।

महिला उद्यमिता मंच

- द वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म भारत की महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम बनाने वाला अपनी तरह का पहला एकीकृत-एक्सेस पोर्टल है।

- ❖ ऐसे मंच का विचार सबसे पहले नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने 2017 में हैदराबाद में आयोजित आठवें ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के समापन पर इसकी स्थापना की घोषणा की थी, जिसका थीम था- 'वूमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेक्टि फॉर ऑल'।
- ❖ एक सक्षम मंच के रूप में, डब्ल्यूईपी के तीन स्तंभ हैं:
 - इच्छा शक्ति, जो अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए इच्छुक उद्यमियों को प्रेरित करती है
 - ज्ञान शक्ति, जो महिला उद्यमियों को ज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्रदान करने का प्रतिनिधित्व करती है, ताकि उन्हें उद्यमशीलता प्रदान करने में मदद मिल सके।
 - कर्म शक्ति, जो व्यवसाय को स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने में उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है।
- ❖ यह मंच महिला उद्यमिता को सक्षम करने के साथ-साथ सूचना संसाधनों और सेवाओं के एक एग्रीगेटर के रूप में काम करते हुए इन उद्देश्यों को पूरा करता है, और आकांक्षी या स्थापित महिला उद्यमियों को एक सुकर अनुभव प्रदान करने के लिए एकीकरण के विभिन्न रूपों का एहसास करने के लिए भागीदार संगठनों के साथ मिलकर काम करता है।

वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2019

- डब्ल्यूईपी ने अपने वेबसाइट के माध्यम से वूमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (डब्ल्यूटीआई) अवार्ड्स के चौथे संस्करण के लिए 2300 से अधिक नामांकन प्राप्त किए।
- द वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर आयोजित किया गया है।
- पुरस्कार देने के पीछे का विचार असाधारण महिला उद्यमियों को दिखाना है कि उन्होंने पुरानी सोच को हटाकर व्यवसायों, उद्यमों और पहलों के माध्यम से चुनौतीपूर्ण रूढ़ियों को चुनौती दी है:
- विकास से संबंधित चुनौतियों का पता लगाने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करना, और/या
- प्रभावित समुदाय
- विशेषज्ञ संगठन और प्रख्यात ज्यूरि सदस्यों के माध्यम से स्क्रीनिंग और मूल्यांकन की पारदर्शी और उच्च उद्देश्य प्रक्रिया के माध्यम से चयनित शीर्ष 15 प्रत्याशियों को दिसंबर 2019 के महीने में आयोजित औपचारिक समारोह में सम्मानित किया गया।

व्यापक रूप से जुड़ा होना: हाइ-प्रोफाइल विजिट

1. पहला भारत-चीन आर्थिक सहयोग मंच

- ❖ पहला भारत-चीन आर्थिक सहयोग मंच भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नीति आयोग और एनडीआरसी के अंतर्राष्ट्रीय निगम विभाजन के साथ 9 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में छोटे रणनीतिक आर्थिक वार्ता के अवसर पर आयोजित की गई थी।

2. दूसरा भारत-रूस सामरिक आर्थिक वार्ता

- ❖ दूसरा भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता (आईआरएसईडी) 10 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और रूसी संघ के आर्थिक विकास के उप मंत्री मयर मकसिमोव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- ❖ इस वार्ता में समानांतर राउंडटेबल्स थे, जिसमें परिवहन बुनियादी ढांचे यथा-कृषिय छोटे और मध्यम व्यापार समर्थनय डिजिटल परिवर्तनय व्यापारय बैंकिंग, निवेशय और पर्यटन और कनेक्टिविटी के मुख्य क्षेत्रों में ठोस रोडमैप बनाने के लिए सहयोग पर चर्चा की गई।

3. सुदूर पूर्व, रूस और आर्कटिक में सहयोग

- ❖ नीति आयोग ने 4 सितंबर 2019 को व्लादिवोस्तोक में पूर्वी सुदूर आर्थिक मंच (ईएफआफ) के दौरान सुदूर पूर्व रूस और आर्कटिक के विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता किया, जहाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- ❖ समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष रूस में सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और 2020-2025 तक आर्कटिक के विकास के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से आगे बढ़ने वाले ईईएफ के आधार पर एक व्यापार मंच की संयुक्त रूप से मेजबानी करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है।

पहला नीति-ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी डायलॉग

- ❖ वर्ष 2017 में नीति आयोग और ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी के बीच आशय विवरण के आधार पर, नीति-ट्रेजरी वार्ता का शुभारंभ 30 अप्रैल 2019 को कैनबरा में आयोजित किया गया था।
- ❖ दोनों पक्ष सीमावर्ती प्रौद्योगिकियों, नियामक सैंडबॉक्स परामर्श, क्षमता निर्माण और नियमित आदान-प्रदान में सहयोग का पता लगाने के लिए सहमत हुए। दूसरी वार्ता 2020 में भारत में आयोजित होने वाली है।

5. नई दक्षिणी नीति संबंधी राष्ट्रपति समिति और नीति आयोग बीच उच्च स्तरीय बैठक

- ❖ कोरिया गणराज्य की नई दक्षिणी नीति संबंधी राष्ट्रपति समिति

के अध्यक्ष और सीईओ, नीति आयोग के बीच उच्च स्तरीय बैठक, 24 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

- ☛ दोनों पक्षों ने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संचार के नियमित चैनल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें मेक इन इंडिया की तर्ज पर विनिर्माण और गतिशीलता बनाए रखना, सीमांत तकनीकी, 5 जी के साथ-साथ स्टार्ट-अप और पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना आदि शामिल हैं।

6. सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच

- ☛ वर्ष 2019 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान में बुलाई गई सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की बैठक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9 से 18 जुलाई 2019 तक आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के महानिदेशक डॉ. राजीव कुमार ने किया था।
- ☛ विषय था लोगों को सशक्त बनाना और समावेशीता तथा समानता सुनिश्चित करना। डॉ. राजीव कुमार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए एक संबोधन में एसडीजी में भारत की प्रगति के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।

थिंक टैंक के साथ नेटवर्किंग

- सामवेश पहल प्रतिष्ठित ज्ञान संस्थानों के साथ नीति आयोग की नेटवर्किंग और ज्ञान साझेदारी पहल है।
- विकास प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने, संस्थागत क्षमता विकास को बढ़ाने और पारस्परिक संवर्धन के लिए समुदाय सहित क्षेत्र-स्तरीय इंटरफेस को सक्षम करने हेतु विचार करता है।
- दिनांक 13-15 मई : 019 के दौरान, भारत में विकास और क्षेत्रीय विकास सामवेश साझेदारी के तहत नवीनतम अनुभवों और उभरते परिप्रेक्ष्य पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- यह सम्मेलन मानव विकास संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसे पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा समर्थित था।
- इस समूह ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शनों, निवेश और वित्तीय प्रवाह और राजकोषीय संघवाद पर विचार-विमर्श किया।